UPSC-CSE 2027/28

DAILY CURRENT AFFAIRS

ONE STOP SOLUTION

By **Faiyaz Sir**



The Indian EXPRESS

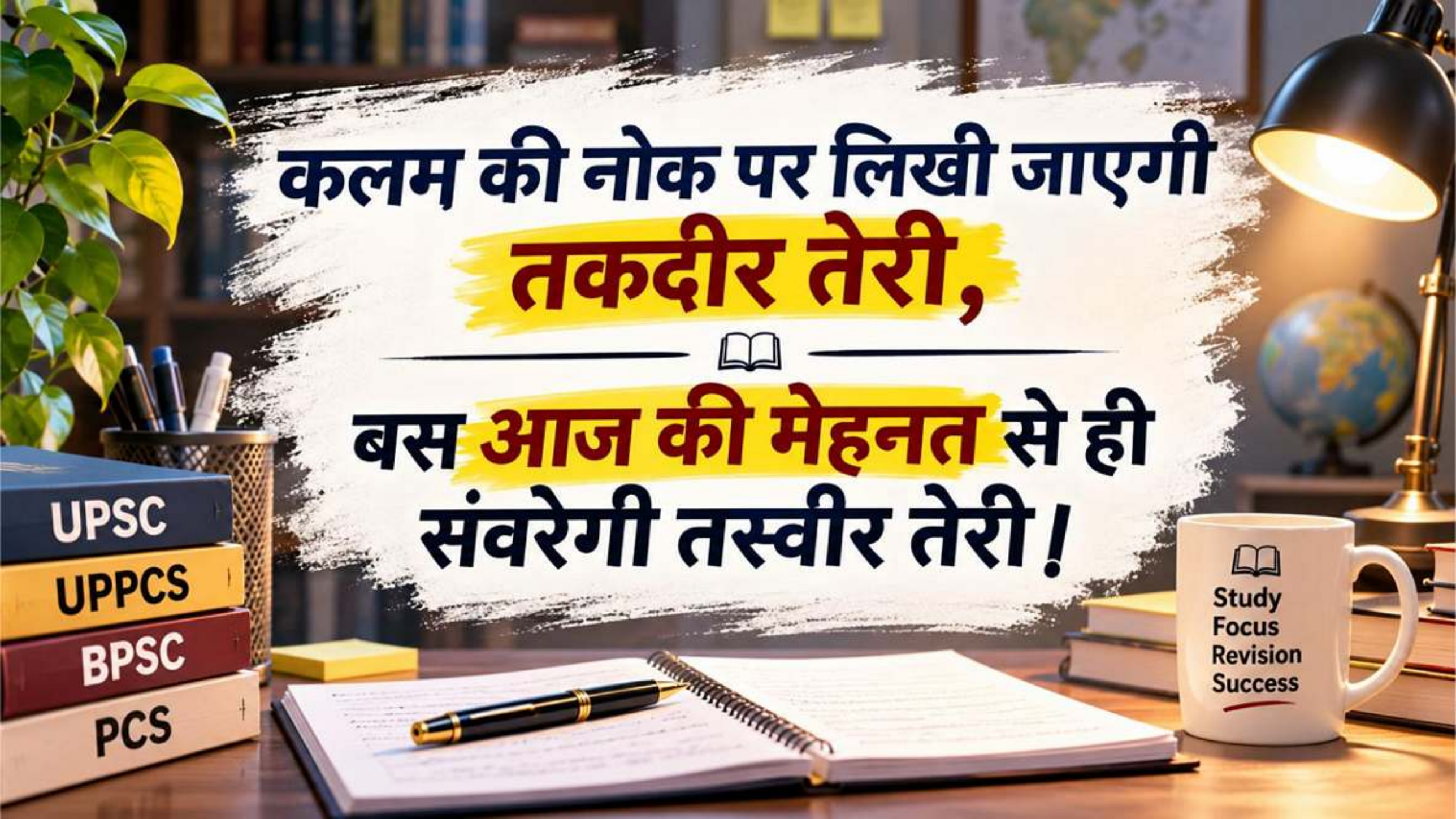
THE HINDU

pib PRESS INFORMATION BUREAU

06 NOVEMBER

COMPLETE COVERAGE | EXAM FOCUSED | ANALYSIS MADE EASY | STATIC + CURRENT INTEGRATION

STAY AHEAD STAY PREPARED


कलम की नोक पर लिखी जाएगी
तकदीर तेरी,
बस आज की मेहनत से ही
संवरेगी तस्वीर तेरी!
UPSC
UPPCS
BPSC
PCS
Study
Focus
Revision
Success

आज क्या पढ़ेंगे?

- Bhartiya Manak Bureau
- Important minerals Process Scheme
- Internet – Right or Ban
- War & Its Ecological Impact
- SC – Arrest and Detention
- ECI – SIR
- Kotia Village
- SPSC Issues
- MDR
- UGC Rule
- Tokamakes
- Israel Election
- Saudi Arab – Houthis
- UN Peace Keeping
- Ronaldo
- PRALAY
- INS Sahyadri
- VB-G RAM G
- IPRD 2026
- 150 Years of Vande Mataram

Result Mitra

पत्र सूचना कार्यालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

Others

भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्किंग

उपभोक्ताओं के विश्वास की पहचान

Posted On: 05 NOV 2026 2:00PM

हॉलमार्किंग उपभोक्ताओं को सोने और चांदी के आभूषणों की शुद्धता का आश्वासन प्रदान करके सोच-समझकर खरीदारी करने में मदद करती है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) निर्धारित मानकों, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी और नियामक जांच के माध्यम से इस व्यवस्था की निगरानी करता है।

वर्ष 2021 में सोने के आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू किए जाने के बाद, 15 अक्टूबर, 2026 तक 65 करोड़ से अधिक सोने के आभूषणों को हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (एचयूआईडी) प्रदान की जा चुकी है। इसी अवधि के दौरान बीआईएस में पंजीकृत जौहरियों की संख्या भी 43,153 से बढ़कर 2,36,624 हो गई है।

चांदी के मामले में हॉलमार्किंग स्वैच्छिक बनी हुई है, लेकिन 1 सितंबर, 2025 से हॉलमार्क वाले चांदी के सभी आभूषणों पर एचयूआईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक 90 लाख से अधिक चांदी की वस्तुओं पर एचयूआईडी के साथ हॉलमार्किंग की जा चुकी है।

बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से डिजिटल सत्यापन और निरंतर निगरानी से उपभोक्ताओं को आभूषणों की शुद्धता जांचने में मदद मिलती है जिससे बाजार में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

Result Mitra

सोना और उपभोक्ता विश्वास की आवश्यकता

- भारतीय परिवारों में पीढ़ियों से सोने का विशेष स्थान रहा है। यह न केवल बहुमूल्य धरोहर के रूप में संजोकर रखा जाता है, बल्कि मूल्यवान संपत्ति के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार अक्सर महंगाई के प्रभाव से अपनी बचत को सुरक्षित रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से सोना खरीदते हैं। हालांकि, सोने के आभूषणों की शुद्धता का सही-सही पता लगाना हमेशा आसान नहीं होता।
- सोना अपेक्षाकृत एक नरम धातु है और आभूषण बनाने और सामान्य उपयोग के दौरान होने वाली टूट-फूट से बचाने के लिए इसमें अन्य धातुओं का मिश्रण किया जाता है हालांकि, यह प्रक्रिया आवश्यक है, लेकिन इससे मिलावट और शुद्धता के बारे में गलत जानकारी देने की आशंका भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा, कई जोड़ वाले जटिल डिजाइन के आभूषणों अथवा सोने की परत चढ़ी वस्तुओं में वास्तविक सोने की मात्रा का निर्धारण करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- सरकार ने उपभोक्ताओं को इस प्रकार की अनियमितताओं से बचाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सोने के उत्पादों के मानकीकरण और देश में हॉलमार्किंग व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए।

हॉलमार्किंग क्या है?

- *हॉलमार्किंग एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण उपाय है जो **निर्धारित मानकों के अनुरूप** कीमती धातुओं से बनी वस्तुओं की शुद्धता को प्रमाणित करता है। यह उपभोक्ताओं को सोच-समझकर खरीदारी का निर्णय लेने में मदद करता है और उन्हें प्राप्त होने वाली वास्तविक शुद्धता से अधिक शुद्धता के लिए भुगतान करने के जोखिम को कम करता है।*

हॉलमार्किंग योजना: स्वैच्छिक से व्यापक पहुंच

- भारतीय स्वर्ण बाजार में नियामकीय व्यवस्था की कमी को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में स्वैच्छिक हॉलमार्किंग योजना शुरू की गई। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को भारत में हॉलमार्किंग योजना के कार्यान्वयन के लिए एकमात्र एजेंसी के रूप में नामित किया गया। उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी बीआईएस को सौंपी गई। इसके साथ ही, बीआईएस को निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और भारत को सोने के आभूषणों के एक अग्रणी वैश्विक बाजार के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करने का दायित्व भी सौंपा गया।
- चांदी की वस्तुओं के लिए हॉलमार्किंग योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई। वर्तमान में भारत में हॉलमार्किंग योजना के अंतर्गत सोना और चांदी, दोनों शामिल हैं।
- सोने के आभूषणों के लिए 23 जून, 202[illegible] से 256 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई। परख एवं हॉलमार्किंग केंद्रों के विस्तार के साथ अब इसका दायरा 392 जिलों तक बढ़ गया है। हॉलमार्किंग की इस व्यवस्था के अंतर्गत आईएस 1417 मानक के तहत सोने की 7 कैरेट श्रेणियां—9 कैरेट (375), 14 कैरेट (585), 18 कैरेट (750), 20 कैरेट (833), 22 कैरेट (916), 23 कैरेट (958) और 24 कैरेट (995)(प्रति हजार भाग में शुद्धता) शामिल हैं।
- चांदी की हॉलमार्किंग अभी भी स्वैच्छिक है, लेकिन बीआईएस की योजना के अंतर्गत हॉलमार्क की गई चांदी की प्रत्येक वस्तु पर 1 सितंबर, 2025 से हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (एचयूआईडी) अंकित करना अनिवार्य है। एचयूआईडी छह अंकों का एक विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है, जिसे हॉलमार्क वाले प्रत्येक आभूषण पर अंकित किया जाता है। इससे आभूषण की पहचान और उसकी ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित होती है।
- संशोधित आईएस 2112:2025 मानक के अंतर्गत चांदी के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग शुद्धता की आठ श्रेणियों—800 (800.0), 835 (835.0), 900 (900.0), 925 (925.0), 958 (958.0), 970 (970.0), 990 (990.0) और 999 (999.0) (प्रति हजार भाग में शुद्धता) में की जा सकती है।

Result Mitra

हॉलमार्क वाले आभूषणों की पहचान कैसे करें

- हॉलमार्क वाले आभूषण या कलाकृतियां खरीदते समय तीन महत्वपूर्ण चिह्नों की पहचान करना आवश्यक है।

सोने के आभूषणों/कलाकृतियों के लिए:

- बीआईएस मानक चिह्न : इस चिह्न पर बीआईएस का लोगो अंकित होता है।
- शुद्धता/फाइननेस चिह्न : यह आभूषण में सोने की शुद्धता दर्शाता है। उदाहरण के लिए, 22के916
- एचयूआईडी (हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या): यह आभूषण को आवंटित छह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है।

चांदी के आभूषणों/कलाकृतियों के लिए:

- बीआईएस मानक चिह्न: इस पर बीआईएस के लोगो के साथ 'सिल्वर' शब्द अंकित होता है।
- शुद्धता/फाइननेस चिह्न : यह चांदी की शुद्धता दर्शाता है। उदाहरण के लिए, 925
- एचयूआईडी (हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या): यह वस्तु को आवंटित छह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है।
- ये तीनों चिह्न मिलकर खरीदे गए आभूषण की शुद्धता के प्रति उपभोक्ताओं को अधिक भरोसा और आश्वासन प्रदान करते हैं। आभूषण की वास्तविक सुंदरता शुद्धता के विश्वास के साथ ही निखरती है।



व्यवहार में हॉलमार्किंग: अनुरोध से सत्यापन तक

- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने हॉलमार्किंग के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित की है, जिसमें जौहरियों का पंजीकरण, शुद्धता का आकलन, डिजिटल पहचान और नियामकीय निगरानी शामिल हैं।



1. पंजीकरण और परीक्षण केंद्र

- हॉलमार्किंग की प्रक्रिया हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने के इच्छुक जौहरियों के बीआईएस में पंजीकरण से शुरू होती है। जौहरी, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल https://www.nsws.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर सीधे अथवा बीआईएस पोर्टल https://www.manakonline.in के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। पंजीकरण तत्काल और निःशुल्क प्रदान किया जाता है तथा इसकी वैधता आजीवन रहती है।
- इसके बाद जौहरियों को अपने आभूषण बीआईएस से मान्यता प्राप्त परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) में जमा कराने होते हैं। एएचसी वे परीक्षण केंद्र हैं, जहां आभूषणों की जांच की जाती है। बीआईएस इन केंद्रों को उनके बुनियादी ढांचे, परीक्षण सुविधाओं और योग्य कर्मचारियों के सत्यापन के बाद मान्यता प्रदान करता है।

2. डिजिटल पोर्टल के माध्यम से हॉलमार्किंग अनुरोध शुरू करना

- जौहरियों को हॉलमार्किंग के लिए आभूषण जमा कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से अनुरोध शुरू करने और आभूषणों को एएचसी तक भेजने की सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पंजीकृत जौहरी www.manakonline.in पर लॉग-इन करके हॉलमार्किंग विकल्प चुन सकते हैं और अनुरोध शुरू कर सकते हैं। इसके तहत उन्हें आभूषणों की श्रेणी, संख्या, वजन, घोषित शुद्धता और चयनित एएचसी जैसे विवरण दर्ज करके अनुरोध जमा करना होता है।
- वैकल्पिक रूप से, यदि जौहरी पोर्टल का उपयोग किए बिना आभूषण जमा कराते हैं, तो एएचसी के कर्मचारी उनकी ओर से अनुरोध शुरू कर सकते हैं। इस डिजिटल प्रक्रिया से जमा कराए गए आभूषणों का रिकॉर्ड तैयार होता है जिससे हॉलमार्किंग की पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

3. परीक्षण और एचयूआईडी

- आभूषणों के परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) पहुंचने के बाद निर्धारित उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके उनके वजन और शुद्धता का आकलन किया जाता है।
- हॉलमार्किंग प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली मशीनों और उपकरणों, जिनमें वजन मापने वाले तराजू, एक्स-रे फ्लोरेसेंस मशीनें और लेजर मार्किंग मशीनें शामिल हैं, में केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर को सीधे डेटा हस्तांतरित करने की सुविधा होना अनिवार्य है। इससे प्रक्रिया के दौरान प्राप्त संबंधित आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जा सकते हैं और मैन्युअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता कम होती है।
- मैन्युअल डेटा प्रविष्टि की संभावना को समाप्त करने के लिए एक्सआरएफ मशीनों का एपीआई आधारित एकीकरण 1 सितंबर, 2024 से लागू किया गया। इसके साथ ही एकीकृत वजन मापन प्रणालियां भी उपलब्ध कराई गई हैं, जो तराजू से प्राप्त रीडिंग को सीधे रिकॉर्ड करती हैं।
- परीक्षण के बाद, बीआईएस सर्वर प्रत्येक आभूषण के लिए छह अंकों का विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड तैयार करता है। इसके बाद बीआईएस मानक चिह्न और संबंधित शुद्धता चिह्न के साथ एचयूआईडी कोड भी आभूषण पर अंकित किया जाता है।
- एएचसी के लिए आभूषण और उस पर अंकित हॉलमार्क, जिसमें एचयूआईडी भी शामिल है, की तस्वीरें लेना भी अनिवार्य है। 8 जून, 2026 को लागू किए गए प्रावधानों के तहत ये तस्वीरें और आभूषणों का वजन सीधे मानक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

4. डिजिटल निगरानी और ट्रेसबिलिटी

- बीआईएस ने पोर्टल पर एएचसी में की जाने वाली गतिविधियों की तारीख और समय दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। ये टाइमस्टैम्प (समय संबंधी विवरण) संचालन की वास्तविक समय में निगरानी करने और हॉलमार्क वाले आभूषणों की प्राप्ति से लेकर उन्हें सौंपने तक लगने वाले समय का आकलन करने में मदद करते हैं। इससे यह जांचने में भी सहायता मिलती है कि लेजर मार्किंग से पहले आभूषणों का परीक्षण किया गया था या नहीं।
- इसके अतिरिक्त, स्वचालित वजन रिकॉर्डिंग और एचयूआईडी हस्तांतरण सुविधा जैसी डिजिटल पहलें हॉलमार्किंग की आपूर्ति श्रृंखला में शुरू से अंत तक ट्रेसबिलिटी को और मजबूत करती हैं। एचयूआईडी हस्तांतरण सुविधा के माध्यम से जब सोने के आभूषण एक जौहरी से दूसरे जौहरी या एक बिक्री केंद्र से दूसरे बिक्री केंद्र तक पहुंचते हैं, तो जौहरी बीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विशिष्ट एचयूआईडी को डिजिटल रूप से हस्तांतरित कर सकते हैं।
- 1 जून, 2026 को लागू किए गए इस सुविधा के पहले चरण में कॉरपोरेट ज्वैलर्स के बीच अथवा किसी भी जौहरी से कॉरपोरेट इकाई को सोना हस्तांतरित किए जाने पर एचयूआईडी हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है। इससे दोहरी हॉलमार्किंग या धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलती है।

5. नियामकीय निगरानी: बिक्री केंद्रों से आगे भी जांच

- डिजिटल निगरानी के साथ-साथ बीआईएस भौतिक निरीक्षण और नियामकीय जांच भी करता है। बीआईएस समय-समय पर आभूषण बिक्री केंद्रों का दौरा करता है और हॉलमार्क वाले आभूषणों के नमूने लेकर संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप उनकी जांच करता है। बीआईएस यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निगरानी ऑडिट भी करता है कि एएचसी निर्धारित आवश्यकताओं का निरंतर पालन कर रहे हैं या नहीं।
- बीआईएस हॉलमार्क के दुरुपयोग से संबंधित प्राप्त शिकायतों और सूचनाओं के आधार पर छापेमारी सहित विभिन्न प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयां भी करता है। ये कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और हॉलमार्किंग व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करने में मदद करते हैं। वर्ष 2025-26 में ऐसे उल्लंघनों के लिए जौहरियों के विरुद्ध 30 से अधिक प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयां की गईं।



6. खरीदारी से पहले सत्यापन: बीआईएस केयर ऐप

- भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ताओं को बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से हॉलमार्क वाले सोने और चांदी के आभूषणों का डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा प्रदान करता है। उपभोक्ता हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (एचयूआईडी) दर्ज करके किसी भी हॉलमार्क वाली वस्तु की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं।
- यह ऐप आभूषण की शुद्धता, उत्पाद के प्रकार, जौहरी तथा परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, 8 जून, 2026 को लागू किए गए डिजिटल उन्नयन के बाद ऐप के माध्यम से आभूषण की तस्वीर, उस पर अंकित हॉलमार्क और स्वचालित रूप से दर्ज किए गए वजन की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। इससे ग्राहक खरीदारी से पहले वास्तविक आभूषण का आधिकारिक रिकॉर्ड में उपलब्ध विवरणों से मिलान कर सकते हैं।
- बीआईएस केयर ऐप एंड्रॉयड और आईओएस पर 12 भाषाओं में निःशुल्क उपलब्ध है।
- इस प्रकार, डिजिटल ट्रेसबिलिटी, उपकरणों का एकीकरण और भौतिक निगरानी मिलकर हॉलमार्किंग व्यवस्था में जवाबदेही को और मजबूत बनाते हैं।

Result Mitra

हॉलमार्किंग: पहुंच और जागरूकता का विस्तार

- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने पंजीकृत जौहरियों और परख एवं हॉलमार्किंग केंद्रों के बढ़ते नेटवर्क के साथ-साथ उपभोक्ता जागरूकता संबंधी पहलों के माध्यम से हॉलमार्किंग के दायरे का विस्तार किया है।
- वर्ष 2021 में सोने के आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू किए जाने के बाद, 15 अक्टूबर, 2026 तक 65 करोड़ से अधिक सोने के आभूषणों पर एचयूआईडी के साथ हॉलमार्किंग की जा चुकी है। इस अवधि के दौरान बीआईएस में पंजीकृत सक्रिय जौहरियों की संख्या 43,153 से बढ़कर 2,36,624 हो गई, जबकि मान्यता प्राप्त परख एवं हॉलमार्किंग केंद्रों (एएचसी) की संख्या 948 से बढ़कर 1,565 हो गई।
- स्वैच्छिक हॉलमार्किंग योजना के अंतर्गत चांदी के लिए 1 सितंबर, 2025 से एचयूआईडी की व्यवस्था शुरू की गई। इसके परिणामस्वरूप, 90 लाख से अधिक चांदी की वस्तुओं पर एचयूआईडी के साथ हॉलमार्किंग की जा चुकी है।
- उपभोक्ता जागरूकता इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीआईएस के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों ने देशभर में 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर, 2026 के दौरान 1,582 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले मानकों, हॉलमार्किंग तथा ग्राम पंचायतों को जागरूक करने से संबंधित कार्यक्रम आदि शामिल थे।



अधिक विश्वास और पारदर्शिता की ओर

- हॉलमार्किंग आभूषणों की खरीदारी के दौरान बहुमूल्य धातुओं की शुद्धता के प्रति उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाती है। पिछले कुछ वर्षों में व्यापक पहुंच, प्रौद्योगिकी के उपयोग और अधिक सुदृढ़ ट्रेसबिलिटी के माध्यम से इस व्यवस्था का विस्तार हुआ है।
- विशिष्ट पहचान कोड आभूषणों से संबंधित विवरणों के सत्यापन में मदद करते हैं, जबकि भौतिक निगरानी और नियामकीय जांच जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक हैं। उपभोक्ता जागरूकता संबंधी पहलें भी खरीदारों को हॉलमार्क वाले आभूषणों की पहचान करने और सोच-समझकर खरीदारी करने में मदद करती हैं।
- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ प्रत्येक हॉलमार्क को विश्वास की पहचान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

Prelims Question (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न)

प्रश्न: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) हॉलमार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 2021 से सोने के आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू की गई है।
2. चांदी के मामले में हॉलमार्किंग को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है।
3. BIS केयर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता आभूषणों की शुद्धता का डिजिटल सत्यापन कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1
- (d) 1, 2 और 3

Mains Question (मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न)

- **प्रश्न:** उपभोक्ता संरक्षण और बाज़ार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) हॉलमार्किंग और HUID (हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या) की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (शब्द सीमा: 150 शब्द)

Result Mitra

पत्र सूचना कार्यालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

Infrastructure

महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना

लिथियम और निकेल घरेलू प्रसंस्करण के लिए 2,814 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन

Posted On: 05 NOV 2026 1:53PM

महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहायता योजना *को हाल ही में 2,814 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। यह योजना* ***वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31*** *तक चलेगी। इसके तहत, दो लिथियम और दो निकेल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए* ***30 प्रतिशत*** *पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों का चयन प्रतिस्पर्धी दो-चरण की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें परियोजना की उपलब्धि को देखते हुए सहायता जारी की जाएगी। इस योजना से* ***लगभग 10,000 करोड़ रुपये*** *का निवेश होने की उम्मीद है। यह आयात निर्भरता को कम करेगा, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को और भी तेज करेगा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिकी, रक्षा और विशेष इस्पात का समर्थन करेगा।*

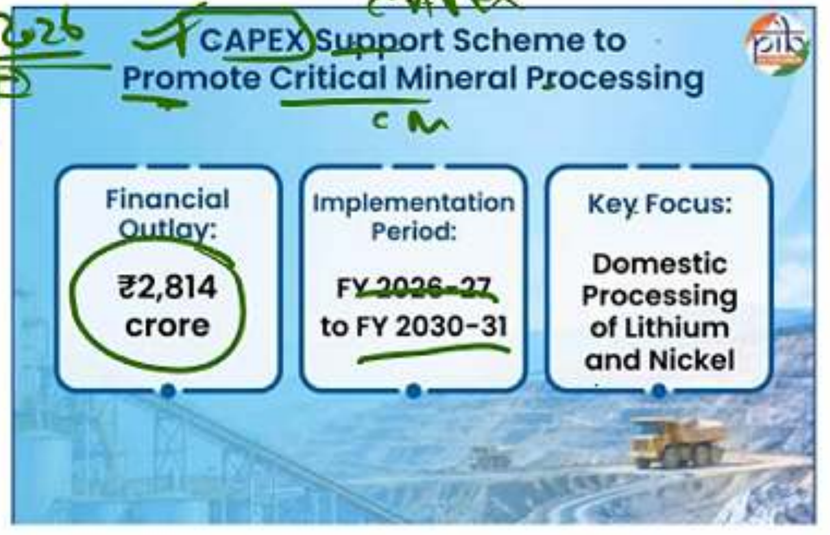
Result Mitra

भारत की महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षमताओं का विकास

- महत्वपूर्ण खनिज आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। वे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिकी, परिवहन, दूरसंचार और रक्षा में योगदान करते हैं। उनकी उपलब्धता कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन खनिजों का प्रसंस्करण भौगोलिक रूप से कुछ देशों में केंद्रित है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भू-राजनीतिक व्यवधानों, मूल्य अस्थिरता और संभावित आपूर्ति प्रतिबंधों के असर को उजागर करता है। नतीजतन, देश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार खनिजों की पहचान करते हैं और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के उपाय करते हैं।
- भारत ने लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और दुर्लभ धातुओं सहित **24 महत्वपूर्ण खनिजों** की पहचान की है। 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए देश की प्रतिबद्धता उनके महत्व को और दर्शाती है। हालांकि, प्रमुख खनिजों की परिष्कृत मध्यवर्ती और उच्च शुद्धता वाली सामग्री के लिए देश की जरूरतों को बड़े पैमाने पर आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। घरेलू प्रसंस्करण में भारत की क्षमताओं को मजबूत करने और बाहरी निर्भरता को कम करने के लिए, **महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहायता योजना** को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 04 नवंबर 2026 को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना

- इस योजना में घरेलू महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए लक्षित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहायता प्रदान की जाती है। इसके प्राथमिक उद्देश्य हैं:
- **घरेलू प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ावा देना:** उच्च शुद्धता वाले लिथियम और निकल प्रसंस्करण संयंत्रों को स्थापित करने में मदद करना। लिथियम संयंत्र अयस्कों और सांद्रता (नमकीन पानी को छोड़कर) को बैटरी-ग्रेड उत्पादों में संसाधित करेंगे, जबकि निकल संयंत्र कोबाल्ट रिकवरी के साथ क्लास-I निकल या बैटरी-ग्रेड निकल सल्फेट का उत्पादन करेंगे। पूंजीगत व्यय समर्थन उच्च अग्रिम लागतों की भरपाई करेगा और परियोजना व्यवहार्यता में सुधार करेगा।
- **एक सुदृढ़ मूल्य श्रृंखला बनाना:** प्रसंस्करण में लापता जुड़ाव को दुरूस्त कर लिथियम और निकल मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना।



वित्तीय परिव्यय और सहायता

- इस योजना का कुल परिव्यय **2,814 करोड़ रुपये है। यह** वित्त वर्ष **2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31** तक पांच साल तक चलेगा। इस योजना के तहत **चार प्रसंस्करण संयंत्र** स्थापित करने के लिए पात्र निवेश के 30 **प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।** इनमें कम से कम **30 किलोटन** क्षमता के दो लिथियम संयंत्र और कम से कम **50 किलोटन** क्षमता के दो निकेल संयंत्र शामिल हैं।
- प्रति लिथियम लाभार्थी **500 करोड़ रुपये** और प्रति निकेल लाभार्थी **900 करोड़ रुपये** तक सहायता सीमित है। यह सहायता लिथियम के लिए 1,000 करोड़ रुपये और निकेल के लिए 1,800 करोड़ रुपये है, जो कुल 2,800 करोड़ रुपये हुआ। इसके अलावा **14 करोड़** रुपये या परिव्यय का 0.5 प्रतिशत प्रशासनिक खर्चों के लिए अलग रखा गया है। इस योजना को पूरी तरह से केंद्र सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।



लाभार्थियों का चयन और प्रोत्साहनों का वितरण

- इस योजना में एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। फिर सहायता चरणों में जारी किया जाएगा जो परियोजना की स्पष्ट उपलब्धियों से से जुड़ा है।
- दो-चरण चयन प्रक्रिया
- **चरण 1 – तकनीकी योग्यता:** सभी आवेदनों का मूल्यांकन तकनीकी मानदंडों पर किया जाएगा। केवल योग्य आवेदक ही अगले चरण में जाएंगे।
- **चरण 2 – वित्तीय बोली:** योग्य आवेदक वित्तीय बोलियां जमा करेंगे। चयन में **कम से कम लागत वाले मानदंड** का पालन किया जाएगा यानी सबसे कम पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
- प्रत्येक खनिज के लिए **दो लाभार्थियों** का चयन किया जाएगा, जिससे कुल चार लाभार्थी हो जाएंगे।

उलब्धि आधार पर सहायता वितरण

- प्रोत्साहन तीन किस्तों में जारी किए जाएंगे। प्रत्येक किश्त विशिष्ट निवेश और इक्विटी उपलब्धि से जुड़ी हुई है।

किश्त	उपलब्धि	जारी की गई संचयी सब्सिडी (उद्धृत बोली राशि का प्रतिशत)
1	प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का 25 प्रतिशत खर्च करने पर न्यूनतम आवश्यक इक्विटी का कम से कम 15 प्रतिशत सहायता मिलेगी	25 प्रतिशत
2	प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का 50 प्रतिशत खर्च करने पर न्यूनतम आवश्यक इक्विटी का कम से कम 50 प्रतिशत सहायता मिलेगी	50 प्रतिशत
3	न्यूनतम आवश्यक इक्विटी के 100 प्रतिशत योगदान के साथ संयंत्र चालू किया जाएगा	100 प्रतिशत

- कमीशनिंग की समयरेखा

- लाभार्थियों को **लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) के तीन साल के** भीतर प्लांट को चालू करना होगा। किसी भी मामले में, **एलओए के पांच साल के भीतर प्लांट की कमीशनिंग होनी ही चाहिए। यदि कमीशनिंग में तीन साल से अधिक की देरी होती है, तो शेष असंवितरित कैपेक्स सहायता पांचवें वर्ष तक एक टेपरिंग तंत्र के अधीन होगा।**

Result Mitra

Prelims Question (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न)

प्रश्न: 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चलेगी।
2. इसके तहत लिथियम और निकल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आयात निर्भरता को बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखला को सीमित करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Mains Question (मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न)

- **प्रश्न:** भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी स्टोरेज और रणनीतिक क्षेत्रों की बढ़ती माँग के संदर्भ में महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के घरेलू प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए उठाये गए कदमों का परीक्षण कीजिए। (शब्द सीमा: 150 शब्द)

महत्वपूर्ण तथ्य

The Hindu

Removing the odds between safety and freedom

Children's internet access must be protected as a fundamental right, with age-appropriate safeguards and shared responsibility to ensure online safety without imposing blanket restrictions

LETTER & SPIRIT

C.B.P. Srivastava

Access to the Internet is essential for ensuring a bright digital future for children and building an inclusive and informed society. However, striking a balance between freedom and safety is the need of the hour. In this regard, the Supreme Court recently, in *Just Rights for Children Alliance v. S. Harish* (2025), has recognised internet access as a fundamental right, emphasising that, particularly for children, the internet serves as a gateway to knowledge, creativity, and self-expression. In the digital era, access to the Internet is a human right and an essential component of the right to freedom of speech and expression guaranteed under Article 19(1)(a) of the Constitution.

The court has observed that the general perception that safety and freedom are at odds with each other is a false notion. Protecting children does not necessarily mean restricting their freedom. The court's observations reinforce democratic principles. However, it is equally important to create an environment in which people in general, and children in particular, can explore the digital world safely while protecting, respecting, and fulfilling their fundamental rights.

'Authority-liberty coordination'

Reasonable restrictions on the exercise of freedoms are important to strike a balance between individual and social interests. This ensures that a constitutionalist approach is followed, whereby the Constitution sets limits on the exercise of State authority as well as citizens' liberty. When the State oversteps these limits, dictatorial tendencies may emerge; when citizens seek to exercise their rights without restraint, an anarchic mindset may prevail. Therefore, it is pertinent to ensure the "authority-liberty coordination" for the smooth functioning of India's democratic governance.

A tool for learning

Digital technologies have been transforming almost all sectors, pushing the world to a faster growth trajectory and contributing greatly to enhancing capabilities by widening choices. While Amartya Sen propounded that capability enhancement would lead to development, Joseph Stiglitz said that transformation, in addition to capabilities, is key to development. These theoretical justifications establish that Internet access can open the golden gate of knowledge for children, provided adequate regulations are in place to govern the content available online. It also enables children to develop technological skills, express their opinions, and connect with people across geographical boundaries. It should therefore be recognised not as a privilege granted to children, but as a matter of right

Some of the countries like Australia, Brazil, China, Indonesia, Malaysia and UAE have restricted the use of social media by children by setting screen time limits and in Brazil particularly the children require to link their social media accounts to a legal guardian. In India, States like Andhra Pradesh and Karnataka have plans to impose screen-time curbs for children. The idea behind such plans is to ensure that access to the internet is subject to responsibility. On many occasions, obscene material is posted as content that needs to be effectively restricted. In the recent ruling, the court has rightly said that we should not imitate the international approach while putting curbs; the balance should be consciously decided.

Earlier, in *Anuradha Bhasin v. Union of India* (2020), the Supreme Court held that freedom of speech and expression, and the freedom to carry on trade or business, through the internet, are protected under Articles 19(1)(a) and 19(1)(g). In another ruling, in *Pragya Prasun v. Union of India* (2025), the court held that excluding persons with disabilities from digital KYC violated Article 21 and that the right to digital access is an intrinsic component of the right to life. It also cited Cricket Association of Bengal (1995), saying that Article 19(1)(a) includes the right to know and to receive and impart information and ideas.

Balancing freedom and safety

Freedom cannot go unrestricted, as it would make society uncivilised. Hence, safety measures need to be blended with it.

Though Internet access offers numerous benefits to children, it also exposes them to serious risks, which *inter alia* include cyberbullying, online harassment, violations of privacy, and frauds of various kinds. Ignoring such dangers would prove detrimental to the fast-changing domestic and global social and cultural milieu. It might also lead to the widening of civilisational advancements and cultural traits. A convergent approach is therefore needed, bringing together parents, the government, educational institutions and the service providers. Age-appropriate boundaries must be set, and awareness of online risks must be raised so that children can make informed decisions without getting into an unsafe environment.

Blanket curbs will ultimately prevent children from getting information across sectors. Instead of curbing children's rights, it would be better to revisit existing systems.

All stakeholders must take steps to restrict harmful content and act more responsibly. Preventive measures are always preferable to curtailing children's right to Internet access as a corrective measure.

(C.B.P. Srivastava is President, Centre for Applied Research in Governance)

YouTube Homework

- Article 21

महत्वपूर्ण तथ्य

सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच विरोधाभास को दूर करना।

- **मूल विषय:** बच्चों के लिए इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है, और उनकी ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना बिना किसी पूर्ण (blanket) प्रतिबंध के सबकी साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए।
- **मुख्य बिंदु:**
- **अदालत का दृष्टिकोण:** सुप्रीम कोर्ट (*Just Rights for Children Alliance v. S. Harish (2026)*) ने यह माना है कि बच्चों के लिए इंटरनेट ज्ञान, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति का द्वार है, और यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य घटक है।
- **प्राधिकरण-स्वतंत्रता समन्वय:** स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए उचित प्रतिबंध जरूरी हैं ताकि अराजकता या तानाशाही प्रवृत्तियों से बचा जा सके।
- **सीखने का एक साधन:** उचित नियमों के साथ इंटरनेट बच्चों को तकनीकी कौशल विकसित करने और सुरक्षित रूप से जुड़ने का अवसर देता है।
- **वैश्विक और स्थानीय प्रयास:** कई देशों और भारतीय राज्यों (जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक) ने बच्चों के लिए स्क्रीन-टाइम सीमा तय करने की योजना बनाई है। हालांकि, बिना सोचे-समझे प्रतिबंध लगाने के बजाय हानिकारक सामग्री को जिम्मेदारी से प्रतिबंधित करना चाहिए।
- **संतुलन और सुरक्षा:** माता-पिता, शैक्षणिक संस्थानों और सेवा प्रदाताओं को मिलकर काम करना चाहिए ताकि बच्चों की स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों बनी रहें।

महत्वपूर्ण तथ्य

The ecological fallout of Israel's war in Gaza

On November 5, 2001, the United Nations General Assembly (UNGA) designated November 6 each year as the International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict. This recognition underscores the far-reaching impacts of environmental damage caused by armed conflict, including degradation of ecosystems and resource depletion well after the conflict period. This impact often extends beyond the limits of national territories and affects future generations.

Considering the importance of the issue, the International Law Commission (ILC), in its report titled 'Protection of the Environment in Relation to Armed Conflicts' (PERAC), adopted 27 draft principles in 2022, which were formally noted by the UNGA on December 7, 2022. The overarching purpose of these principles is to enhance the protection of the environment in relation to armed conflicts. The first principle of the PERAC provides that the principles apply to the protection of the environment before, during and after an armed conflict, including in situations of occupation. In this context, Israel's responsibility for internationally wrongful acts causing environmental harm arises not only from its ongoing genocide in Gaza but also from its continuing role as an occupying power.



Abdullah Yasir

Associate Professor at the Centre for International Legal Studies, Jawaharlal Nehru University

The destruction of Gaza's ecosystems underscores the need for accountability under international law

The devastation in Gaza

In its report released on September 23, 2025, titled the 'Environmental Impact of the Conflict in the Gaza Strip', the United Nations Environment Programme (UNEP) documented that two years of escalating hostilities have resulted in unprecedented environmental devastation in Gaza, severely affecting its soils, freshwater resources, and coastline. It says that since 2023, Gaza has lost 97% of its tree crops, 95% of its shrubland, and 82% of its annual crops, leaving its population on the brink of famine.

Freshwater resources are critically scarce, and much of the remaining supply is contaminated. The destruction of sewage treatment facilities, piped water systems, and the increasing reliance on cesspits have likely worsened pollution of the aquifer that provides most of Gaza's water. The UNEP further notes that marine and coastal environments are also likely contaminated.

Approximately 78% of Gaza's estimated 2,50,000 buildings have been damaged or destroyed, resulting in around 61 million tonnes of debris. The loss of vegetation cover and soil compaction from military activity have further degraded soil quality, reducing its capacity to absorb water, heightening flood risks, and limiting groundwater recharge. The UNEP report does not capture the full extent of the environmental devastation in Gaza, as the situation continues to deteriorate and statistics are rapidly rendered obsolete amid Israel's ongoing genocidal assault.

Violations of environmental obligations

As an occupying power, Israel is obligated under the PERAC principles to administer and use the natural resources in an Occupied Palestinian Territory (OTP), for the benefit of the protected population of the occupied territory, while ensuring respect for and protection of the environment. It must integrate environmental considerations into the administration of the OTP.

Nevertheless, Israel has engaged in the systematic extraction of natural resources from the OPT and transferred them to itself, resulting in significant environmental degradation; this has been acknowledged by the International Court of Justice in its advisory opinion of July 19, 2024, 'Legal Consequences Arising from the Policies And Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem'.

Such practices not only contravene environmental protection obligations but also infringe upon the Palestinian people's collective rights, including their permanent sovereignty over natural resources and their right to self-determination. International law affirms that all peoples, including those under occupation, have permanent sovereignty over natural resources, imposing strict limitations on the actions of occupying powers regarding these natural resources. Yet, Israel's prolonged occupation – characterised by territorial expansion, settlement construction, and systematic resource appropriation – has consistently undermined these foundational principles of international law.

Principle 9 of the PERAC stipulates that a state that commits an internationally wrongful act in relation to an armed conflict, resulting in environmental damage, bears international responsibility and is obligated to provide full reparation for such damage, including damage to the environment itself. Accordingly, Israel bears an obligation under international law to provide full reparation for the environmental destruction it has caused in Gaza – an obligation reaffirmed by the International Court of Justice in its advisory opinion of July 19, 2024, 'Legal Consequences Arising from the Policies And Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem'.

The overall picture of occupation

On this International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict, it is critical to acknowledge that the devastation inflicted on Palestine, beginning with the formation of the state of Israel and its ongoing settler-colonial project, constitutes a serious breach of international law. This has become more pronounced since October 7, 2023 when Hamas-led attacks on Israel were followed by Israel's genocidal attack on Gaza.

As Swedish climate activist Andreas Malm aptly observes, the destruction of Palestine is the destruction of the earth. The international community must recognise that climate justice is impossible without dismantling Israel's settler-colonial structure and ensuring the liberation of Palestine.

YouTube Homework

"UN-appointed Independent International Commission of Inquiry on Occupied Palestine

महत्वपूर्ण तथ्य

- गाजा में इजरायल के युद्ध का पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत इजरायल का उत्तरदायित्व।
- **अंतरराष्ट्रीय दिवस और PERAC सिद्धांत:** 6 नवंबर को 'युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने का अंतरराष्ट्रीय दिवस' मनाया जाता है। 2022 में ILC द्वारा अपनाए गए 27 PERAC (सशस्त्र संघर्षों के संबंध में पर्यावरण का संरक्षण) सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण संघर्ष से पहले, दौरान और बाद में होना चाहिए।
- **गाजा में पर्यावरण का विनाश:** UNEP (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) की रिपोर्ट के अनुसार, गाजा में 97% वृक्ष फसलें, 95% झाड़ियां और 82% वार्षिक फसलें नष्ट हो चुकी हैं। लगभग 78% इमारतें क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गई हैं, जिससे 6.1 करोड़ टन मलबा जमा हो गया है और मीठे पानी व तटीय क्षेत्रों में भारी प्रदूषण फैल गया है।
- **पर्यावरणीय दायित्वों का उल्लंघन:** कब्जे वाली शक्ति (Occupying Power) के रूप में इजरायल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है और पर्यावरण संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है।
- **मुआवजा और जवाबदेही:** अंतरराष्ट्रीय कानून और ICJ (अंतरराष्ट्रीय न्यायालय) की सलाहकारी राय (19 जुलाई 2024) के अनुसार, इजरायल इस पर्यावरणीय विनाश की पूर्ण भरपाई और मुआवजा देने के लिए बाध्य है।

महत्वपूर्ण तथ्य

24-hour countdown for hearing starts moment an individual is detained: SC

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Thursday ruled that an arrest occurs the moment an official "touches" an individual to restrain their liberty, immediately triggering the 24-hour countdown to produce them before a Judicial Magistrate.

A Bench headed by Justice Ujjal Bhuyan said the word 'arrest' is not defined in the penal statutes, past or present, from the colonial Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure or its successor, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita of 2023.



Ambiguity in the definition of 'arrest' has allowed law enforcement agencies to detain a person for days on end, the Bench ruled. PTI

Ambiguous definition

The Bench pointed out that the ambiguity in the definition of 'arrest' has allowed law enforcement agencies to detain a person for days on end, employ third-degree measures, including torture, to squeeze out confessions, before the formal arrest is recorded.

Once formal arrest is recorded, Article 22(2) of the Constitution requires the arrested person to be produced before a Judicial Magistrate, giving the person an opportunity of a hearing.

So far, law enforcement officers and police have calculated the 24-hour rule from the time of formal arrest after search and seizure. The hours and days of prior detention were not taken into account.

Changing the script, Justice Bhuyan said the perceived dichotomy between detention and arrest has led to grave human rights violations.

"The tendency to detain suspects for questioning and manipulating the record to show a later time of arrest is a reprehensible practice... What the investigating officers do, in such cases, is to procure statements by assault, illegal detention and fear of continued detention... The worst violations of human rights take place during the course of investigation," the court observed.

The 24-hour period was a constitutional safeguard intended to act as a safety barrier to check such Executive excess.

Mandate in Article 22

"The 24-hour timeline as mandated under clause (2) of Article 22 of the Constitution would commence from the date and time of detention of the person and when his liberty stands curtailed, and not from the time of his formal arrest," Justice Bhuyan held.

Justice Bhuyan reasoned that the Constitution did not recognise detention debors (outside) arrest. "Even if a person is touched with a view to detaining, it would amount to an arrest... Thus, the prescription of 24-hour time period would commence the moment a person is detained by the arresting authority suspecting him to have committed an offence, when his liberty is effectively curtailed," Justice Bhuyan said.

The court held that the fundamental rights to life and liberty as enshrined in Article 21 were at the core of Constitutional jurisprudence, and "cannot be tinkered with so lightly, not even under the special statutes".

"Article 22(2) does not sanction the creation of any buffer zone where the liberty of an individual is curtailed for investigating purposes, but not formally shown as arrested. Creation or contemplation of such a buffer zone is unconstitutional," the court held.

Direction to Magistrates

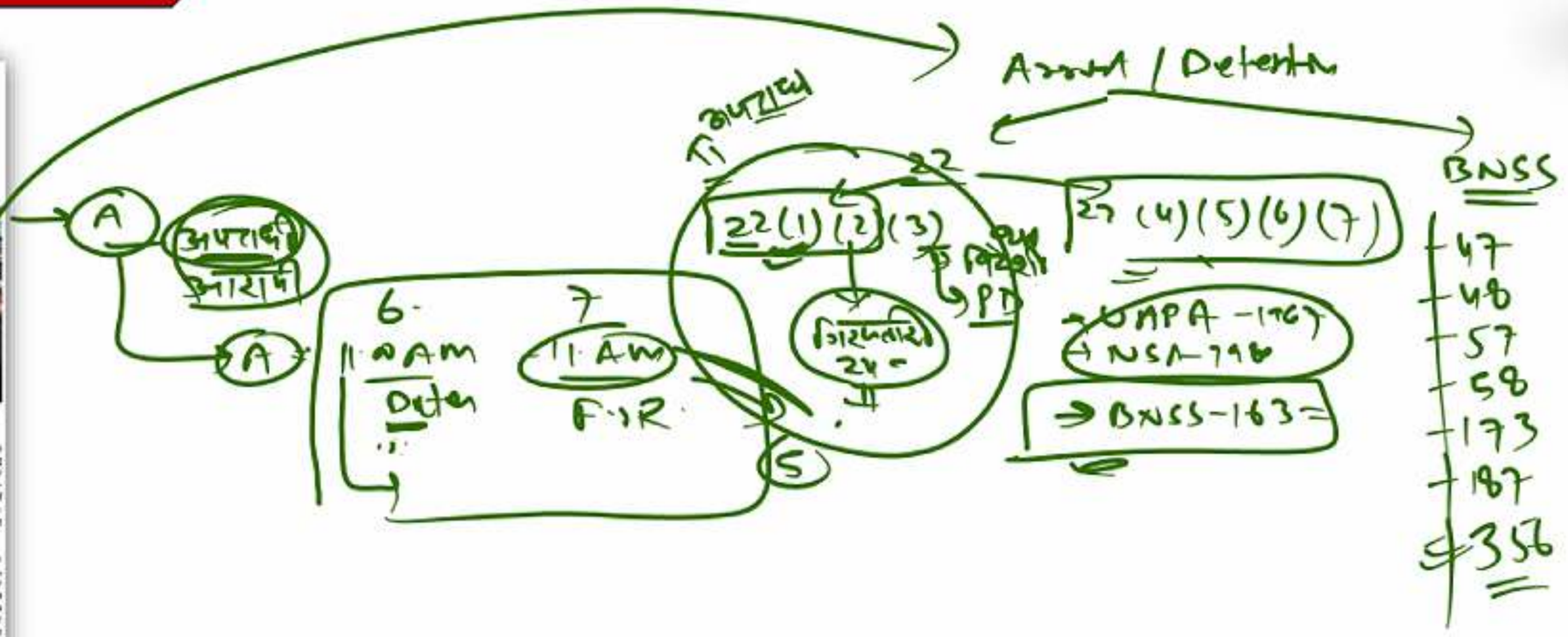
In a series of directions, the court ordered that any person found to have been detained beyond 24 hours by a Magistrate on his or her production, must be released immediately.

The Bench directed that no other time period, except the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the Magistrate, must be excluded from the 24-hour timeline.

The Magistrate concerned was duty-bound to record the actual date and time of detention of the person produced before the court.

The Supreme Court gave Magistrates the discretion to order the release of individuals who were detained for more than was actually reasonable, even if the period had not exceeded 24 hours.

The court was deciding appeals filed by four accused persons in a narcotics case whose formal arrest was recorded only 18 hours later. The Tripura High Court had denied them bail, but the apex court ordered their release forthwith.



महत्वपूर्ण तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने पुलिस हिरासत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

1. यह जजमेंट किस Writ में आया है?

- यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में दायर एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition - SLP (Crl.) Nos. 12451–12453/2026) के रूप में आया है। हालांकि, यह मामला मूल रूप से आरोपियों की गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ और रिहाई की मांग को लेकर निचली अदालत से होते हुए हाईकोर्ट की जमानत याचिकाओं और बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतिम व्यवस्था दी है।
- क्या हुआ था: यह मामला त्रिपुरा का है। 29 सितंबर 2025 को दोपहर लगभग 2:30 बजे जांच एजेंसी ने नशीले पदार्थों (11.03 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन टैबलेट) की बरामदगी के बाद चार आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया था।
- विवाद की वजह: पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में तो 29 सितंबर को ही ले लिया था और उनकी तलाशी व जब्ती शाम 5:00 बजे पूरी हो गई थी। लेकिन पुलिस ने कागजों पर उनकी औपचारिक गिरफ्तारी (Formal Arrest) अगले दिन, यानी 30 सितंबर 2025 को सुबह 11:15 बजे दिखाई। इसके बाद आरोपियों को 30 सितंबर को शाम 4:45 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।
- आरोपियों की दलील: आरोपियों का कहना था कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) का सीधा उल्लंघन है। police ने 24 घंटे की समय-सीमा से बचने के लिए जानबूझकर औपचारिक गिरफ्तारी दिखाने में 18 घंटे की देरी की थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

- सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा हिरासत और गिरफ्तारी के बीच बनाए जाने वाले बनावटी अंतर को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
- समय-सीमा हिरासत से शुरू होगी, गिरफ्तारी से नहीं: अदालत ने साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समय-सीमा उसी पल से शुरू हो जाती है जब पुलिस उसे हिरासत में लेती है (यानी जब उसकी आज़ादी पर रोक लगती है), न कि तब से जब पुलिस कागजों पर उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करती है।
- हिरासत और गिरफ्तारी में कोई बनावटी अंतर नहीं: कोर्ट ने कहा कि आज़ादी में कोई 'अस्थायी निलंबन' जैसी चीज़ नहीं होती। पुलिस सर्च और जब्ती के नाम पर किसी को हिरासत में रखकर 24 घंटे की संवैधानिक सुरक्षा को टाल नहीं सकती। 18 घंटे तक बिना न्यायिक निगरानी के किसी को हिरासत में रखना सत्ता का स्पष्ट दुरुपयोग है।
- 24 घंटे से ज़्यादा रखने पर तुरंत रिहाई: यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के बाद यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, तो उसकी आगे की हिरासत अवैध मानी जाएगी और उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।
- मजिस्ट्रेटों के लिए सख्त निर्देश: देश के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे रिमांड देते समय पुलिस कागज़ात पर नहीं, बल्कि हिरासत में लिए जाने की वास्तविक तारीख और समय को खुद रिकॉर्ड करें। वे स्वतंत्र रूप से जांच करें कि 24 घंटे के नियम का पालन हुआ है या नहीं, और यदि हिरासत की अवधि अनुचित लगती है, तो वे रिमांड देने से इनकार कर सकते हैं।
- हिरासत में यातना पर चिंता: कोर्ट ने ऐतिहासिक डीके बसु मामले का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा मानवाधिकारों का सबसे गंभीर उल्लंघन है और यह देश की एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है, जिसे रोकना कोर्ट का हमेशा प्रयास रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

ECI announces Summary Revision for 6 States, U.T.s

The annual SSR seeks to enrol eligible voters, especially first-timers; election body says furnishing Aadhaar details in Forms 6 and 8 will remain voluntary; draft rolls are to be published on Nov. 30

The Hindu Bureau
NEW DELHI



Making it count: Youth throng a special voter enrolment camp at a college in New Delhi in September. SUSHIL KUMAR VERMA

The Election Commission of India (ECI) on Thursday announced the annual special summary revision (SSR) of electoral rolls for six States and Union Territories — Arunachal Pradesh, Mizoram, Odisha, Sikkim, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu — where the special intensive revision (SIR) has been completed and the final rolls published.

Earlier on October 15, the SSR was announced for 17 States and Union Territories, including poll-bound Uttarakhand, Uttar Pradesh, Punjab, Manipur, and Goa. The SSR, an annual exercise, has not been carried out amid the launch of the now controversial SIR of electoral rolls last year. Election Commissioners S.S. Sandhu and Vivek Joshi are understood to have raised this as an anomaly as well among other issues.

The annual SSR seeks to enrol eligible voters, particularly young and first-time electors, and facilitate advance applications from those who will become eligible on April 1, July 1, and October 1, 2027.

The draft electoral rolls will be published on November 30 this year and the final ones on January 21, 2027.

Furnishing Aadhaar details in Forms 6 and 8 will remain voluntary. No application for enrolment can be rejected, nor can an existing entry be deleted, for failure to provide Aadhaar, according to the SSR order issued by the ECI.

Unlike the contentious SIR process, when enrolling through the SSR, voters do no need to give any documentation proving citizenship or be mapped with earlier electoral rolls.

Among the firsts, in this year's SSR, the ECI has directed that, at the time of polls, "readable PDF" of the alphabetically arranged electoral rolls in pen drive or any other electronic storage device can be provided to the contesting candidates.

This is crucial as Opposition parties have been demanding machine-readable electoral rolls rather than image-based PDFs, so that they are digitally searchable, indexable, and verifiable.

Political parties would also be provided with supplementary voter lists, which were earlier kept only for record and future use.

The SSR process this time would not include house-to-house visits by booth-level officers (BLOs). Instead, both draft as well as final lists would be put up at polling booths.

ECI restores oversight of IT wing after workflow issue

Sreeparna Chakrabarty
NEW DELHI

More than three months after the row over movement of Information Technology head Seema Khanna's files, the Election Commission of India has issued a fresh order bringing back oversight over her department through a Deputy Election Commissioner (DEC).

An internal order issued on July 28 by Senior DEC Maneesh Garg had removed DEC Sanjay Kumar from the charge of IT and Information and Communication Technology (ICT) divisions, and given Dr. Khanna a free hand, enabling her to directly report to the Commission. Following this, two Election Commissioners, S.S. Sandhu and Vivek Joshi, had written to Cabinet Secretary T.V. Somanathan on July 29 regarding the work allocation order of Dr. Garg, who had held interim charge of the Administration Department.

As per the current order, dated October 4, Dr. Khanna is required to route the files related to IT, ICT and Grievances/Public Grievance Redressal System (PGRS) through Senior DEC Pawan Kumar Sharma. Dr. Khanna joined the ECI in 2025 on deputation from the National Informatics Centre (NIC). She heads the commission's IT department and oversees its digital infrastructure, including systems for electoral roll management.



S.S. Sandhu (right) and Vivek Joshi (right) had written to the Cabinet Secretary voicing concern on a work order issued in July. PTI

'No change'

ECI sources though insisted that there is no change in the reporting structure of Director-General of IT as she has always been reporting to a DEC level officer. In an affidavit filed in the Supreme Court, the ECI had maintained that the July 28 order had never been implemented. The sources also said that the work allocation orders were issued as per unanimous decisions of the Commission.

The letters to the Cabinet Secretary by Dr. Sandhu and Dr. Joshi, obtained under the Right to Information (RTI) Act by transparency activist Commodore Lokesh Batra (retired), explained their objections regarding Dr. Garg changing the work allocation of officers "within hours of" getting charge of the administration wing "without discussing or informing" them despite "repeated and explicit oral and written" instructions to all officers.

Both ECs had also said that Dr. Garg had "issued similar orders on one earlier occasion" while he was working as DEC (Administration).

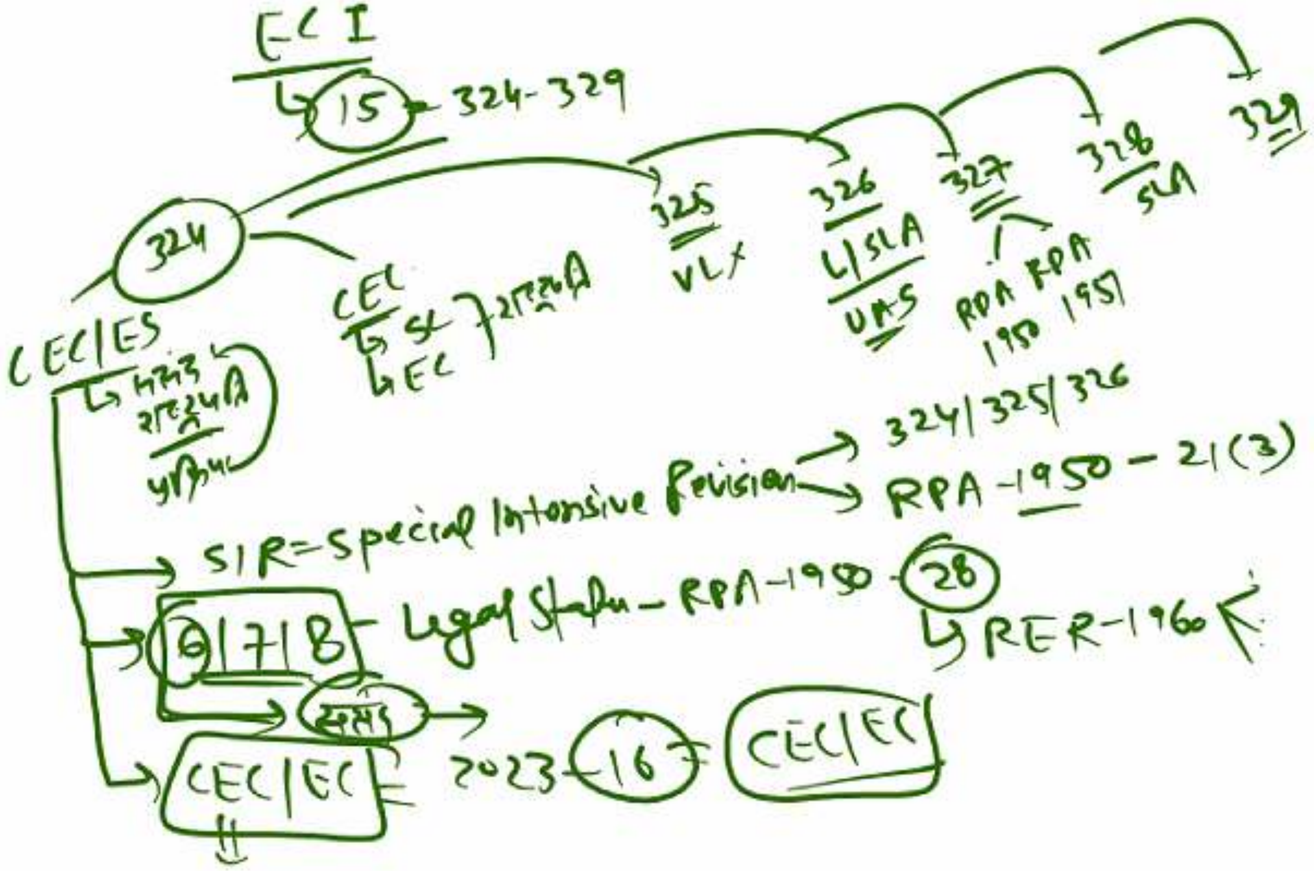
Delimitation in-charge

Prakash Rajpurohit, an IAS officer of the 2010 batch, who was appointed as DEC in the ECI, filling the vacancy caused by the premature repatriation of Sanjay Kumar (earlier in-charge of the electoral rolls and IT divisions), would now be assisting Dr. Garg in election planning. He would also be in-charge of delimitation.

Mr. Kumar, who had been DEC from August 2024 till August this year, was responsible for the electoral rolls and IT divisions of the ECI, and had signed the ECI's June 24, 2025, order initiating the SIR in the country.

महत्वपूर्ण तथ्य

- BNSS Section 163
- Article 19 (1)
- Article 19 (3)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- ECI
- CEC – EC's
- SIR
- RPA 1950 – 21(3)
- RPA 1950 – 28 (RER-1960 - 6,7,8)
- RPA 1951 - 29(A)
- Conduct of Election Rules 1961 – 4(A) – Form 26



महत्वपूर्ण तथ्य

Residents of disputed villages in Kotia cross Odisha boundary to vote in Andhra Pradesh polls

Satyasundar Barik
BHUBANESWAR



Odisha government had deployed 16 platoons of police and erected checkpoints, restricting people's entry and exit. SPECIAL ARRANGEMENT

Several voters from Kotia gram panchayat, whose jurisdiction has long been disputed between Odisha and Andhra Pradesh, crossed the Odisha boundary on Thursday to cast their votes in the mandal parishad territorial constituency and zilla parishad territorial constituency elections conducted by the Andhra Pradesh State Election Commission.

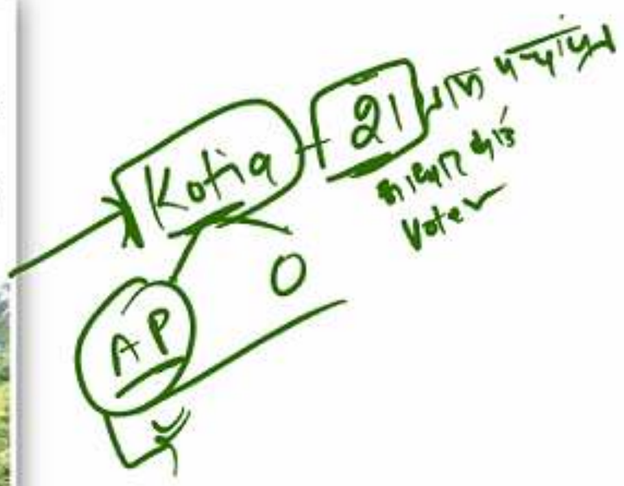
The Odisha government had deployed 16 platoons of police and erected three border checkpoints, restricting people's entry and exit. However, several voters sneaked out from the borders to cast votes.

The Andhra Pradesh government had set up a polling booth for villagers of Kotia at Sariki in its State boundary.

Political parties in Odisha accused leaders from Andhra Pradesh of bribing people to get their votes. "Some were taken to the other side of the boundary on Wednesday. After casting their votes, they returned," said veteran Congress MLA Tara Prasad Bahinipati, who hails from Koraput district.

Similarly, Bhrugu Buxipatra, a senior BJD leader, said a few had crossed borders to vote. However, this time, the people of Odisha were successful by not letting Andhra Pradesh set up its polling booth inside Odisha, he said.

Koraput Sub-Collector Fabi Rasheed said security personnel and Executive Magistrates were deployed in boundary villages to prevent untoward incidents. "Villagers did cross the border, but we have no idea if they voted in the Andhra Pradesh elections," Ms. Rasheed said.



महत्वपूर्ण तथ्य

- कोटिया सीमा विवाद (Kotia Border Dispute) ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच का एक बेहद संवेदनशील और दशकों पुराना क्षेत्रीय विवाद है। यह विवाद मुख्य रूप से ओडिशा के कोरापुट जिले के पोट्टांगी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली कोटिया ग्राम पंचायत के 21 गांवों पर प्रशासनिक अधिकार को लेकर है।

1. यह विवाद क्या है? (What is the dispute?)

- कोटिया ग्राम पंचायत में कुल 28 गांव हैं। इनमें से 21 गांवों पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य अपना-अपना दावा ठोकते हैं।
- ओडिशा का पक्ष: ओडिशा का दावा है कि ये गांव उसके कोरापुट जिले (पोट्टांगी ब्लॉक) का हिस्सा हैं। ओडिशा यहाँ दशकों से स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस स्टेशन जैसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चला रहा है।
- आंध्र प्रदेश का पक्ष: आंध्र प्रदेश इन गांवों को अपने पार्वतीपुरम मान्यम जिले (सालूर मंडल) का हिस्सा बताता है। आंध्र प्रदेश भी इन गांवों में अपनी कल्याणकारी योजनाएं, बिजली और राशन जैसी सुविधाएं देकर अपना दावा मजबूत करता है।
- दिलचस्प स्थिति: इस विवाद के कारण यहाँ के लगभग 5,000 निवासियों के पास दोनों राज्यों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हैं। यहाँ के लोग दोनों राज्यों के चुनावों में मतदान करते हैं और दोनों सरकारों की योजनाओं का लाभ उठाते हैं।

2. विवाद कब से शुरू हुआ? (History of the dispute)

- इस विवाद की जड़ें 1936 में ओडिशा (उड़ीसा) राज्य के गठन और उसके बाद के दौर से जुड़ी हैं:
- 1936-1942: जब 1936 में मद्रास प्रेसीडेंसी से अलग करके ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया, तब इन पहाड़ी गांवों की सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण (सर्वे) नहीं हो पाया था। 1942 के एक सीमांकन (गिल्बी सर्वे) को आधार बनाकर आंध्र प्रदेश इन पर अपना हक जताता है।
- 1955 में पहली बार टकराव: यह विवाद खुलकर तब सामने आया जब 1953 में आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, 1955 में आंध्र के प्रशासनिक अधिकारियों ने इन गांवों से भू-राजस्व (Land Revenue) वसूलने का प्रयास किया, जिसका ओडिशा ने कड़ा विरोध किया।
- कोर्ट का रुख (1968 और 2006): ओडिशा सरकार इस मामले को 1968 में सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। मार्च 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दो राज्यों के बीच सीमा रेखा तय करने का अधिकार केवल देश की संसद के पास है। कोर्ट ने दोनों राज्यों को इस क्षेत्र में यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का निर्देश दिया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. मुख्य मुद्दा क्या है? (What are the core issues?)

- प्रशासनिक नियंत्रण और क्षेत्रीय संप्रभुता: दोनों राज्य यह साबित करना चाहते हैं कि भौगोलिक और कानूनी रूप से यह क्षेत्र उनका है।
- प्राकृतिक संसाधन: यह पहाड़ी इलाका खनिज संसाधनों (Mineral Resources) से समृद्ध माना जाता है, जो दोनों राज्यों के आकर्षण का एक बड़ा कारण है।
- चुनाव और राजनीतिक वर्चस्व: जब भी कोई राज्य यहाँ स्थानीय निकाय या पंचायत चुनाव कराने की कोशिश करता है, तो दोनों राज्यों की पुलिस और प्रशासन आमने-सामने आ जाते हैं।

4. वर्तमान स्थिति क्या है? (Current Status - November 2026)

- नवंबर 2026 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस विवादित कोटिया क्षेत्र में मंडल परिषद (MPTC) और जिला परिषद (ZPTC) के चुनाव कराने की घोषणा के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है:
- पुलिस और प्रशासन में झड़प: 3 नवंबर 2026 को अंतर-राज्यीय सीमा (जैसे नेराडिवलसा चेकपोस्ट) पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस और झड़प हुई।

महत्वपूर्ण तथ्य

BJP leaders meet President over 'irregularities' in KPSC

They urge Murmu to act on former Kerala Governor's recommendation to remove PSC Chairman; despite securing ranks, youth have been denied jobs because of the maladministration, they say

The Hindu Bureau
NEW DELHI

A Bharatiya Janata Party (BJP) delegation on Thursday met President Droupadi Murmu and requested her to act on the recommendation of former Keralam Governor Rajendra Vishwanath Arlekar for the removal of State Public Service Commission (KPSC) Chairman M.R. Baiju and its members over alleged irregularities.

The BJP delegation led by Rajya Sabha member (nominated) C. Sadanandan included State party president Rajeev Chandrasekhar and Rajya Sabha member P.T. Usha.

The former Governor had flagged alleged irregularities in the functioning of the organisation which is responsible for recruitment to government services in the State before demitting office.



Seeking action: President Droupadi Murmu with BJP leader Rajeev Chandrasekhar, and P.T. Usha and C. Sadanandan, MPs. PTI

At a press conference, Mr. Chandrasekhar accused the Congress and Leader of the Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi of raising "manufactured issues" related to the youth, while not addressing their plight in Keralam.

"It reflects hypocrisy and double standards on the part of the Congress, much like the special intensive revision (SIR) issue, where they take one position in Delhi against the SIR but take another position in Keralam in favour of it," he said.

The senior BJP leader said: "This is an important issue that impacts the future of many Malayali youth who have been sitting in protest and on strike for the last several months. Despite appearing for examinations and securing ranks, they have been denied jobs because of the maladministration of the PSC and what we believe is its complete capture by vested interests such as the SFI, which is part of the CPI(M) ecosystem."

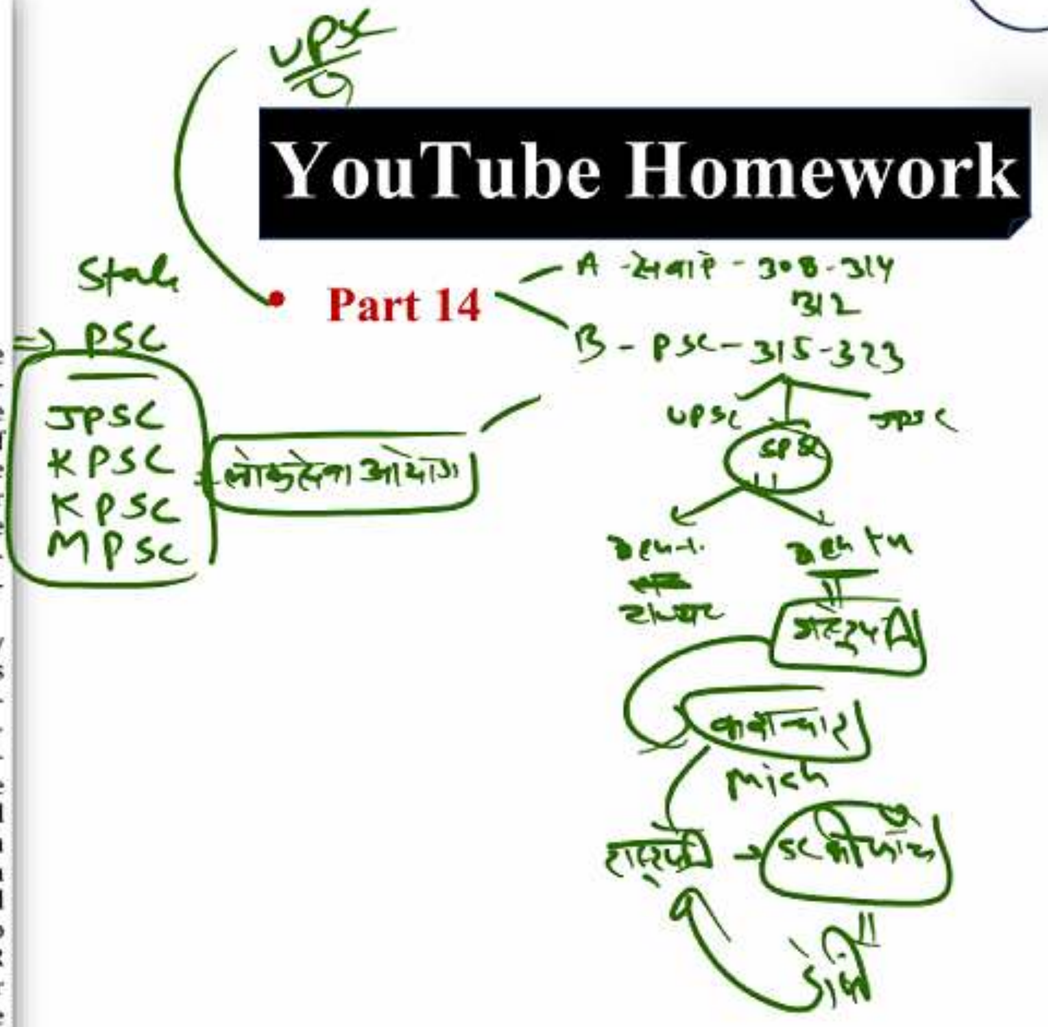
"PSC rank holders have been protesting outside the Secretariat for months, with the full knowledge of the Congress Chief Minister," he said.

KPSC chief, others named in FIR over exam fraud

The Hindu Bureau
THIRUVANANTHAPURAM

The Crime Branch of the Keralam Police has registered an FIR against the Chairman and members of the Kerala Public Service Commission (KPSC) over alleged irregularities in the examination for recruitment to the post of Fisheries Extension Officer.

The latest FIR explicitly identifies three categories of accused: the PSC Chairman, members and officials. The alleged irregularities relate to the examination conducted for the Fisheries Extension Officer post at the Kerala University of Fisheries and Ocean Studies. It has also registered another FIR against PSC members over alleged irregularities in the exam for recruitment to the post of Assistant Motor Vehicle Inspector.



महत्वपूर्ण तथ्य

Merchant charge has been imposed to save UPI ecosystem, NPCI tells SC

'Zero Merchant Discount Rate' for all UPI transactions is no longer sustainable as functional costs would burn into the public exchequer, says payments body in affidavit; the fee will apply to only about 4% of merchant transactions, it adds

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The National Payments Corporation of India (NPCI) has said in the Supreme Court that "zero Merchant Discount Rate (MDR)" for all Unified Payments Interface (UPI) transactions was no longer sustainable, as functional costs for the phenomenally expanding digital payment industry in India would burn into the public exchequer.

UPI processed as many as 24.51 billion transactions, cumulatively worth approximately ₹29.82 lakh crore, in the month of August 2026 alone, marking its highest-ever monthly volume. An average of approximately 791 million transactions were processed every single day in that month. In Financial Year 2025-26, UPI processed approximately 241.62 billion transactions worth approximately ₹314 lakh crore, the NPCI said.

"The figures illustrate not merely growth, but growth of a magnitude that places correspondingly greater demands on the security, resilience, and infrastructural capacity of the system," the NPCI, represented by Additional Solicitor-General N. Venkataraman, submitted in court.



UPI processed 24.51 billion transactions, cumulatively worth about ₹29.82 lakh crore, in the month of August 2026 alone. REUTERS

Legal challenge

The NPCI was responding to a challenge in court to the government's decision to introduce an MDR of 0.4% on Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions above ₹2,000.

Person-to-person (P2P) transactions, which account for 70% of total UPI transaction value, would remain completely free irrespective of amount, the NCPI said. There would be no transaction or platform fee or other charge permissible for individuals for sending or receiving money through UPI, it added.

It said person-to-merchant (P2M) payments up to ₹2,000 would also remain "entirely free of MDR". "This threshold is calibrated to shield the overwhelming majority of everyday, low-value merchant payments of the kind made by ordinary consumers and small merchants alike," the NPCI said.

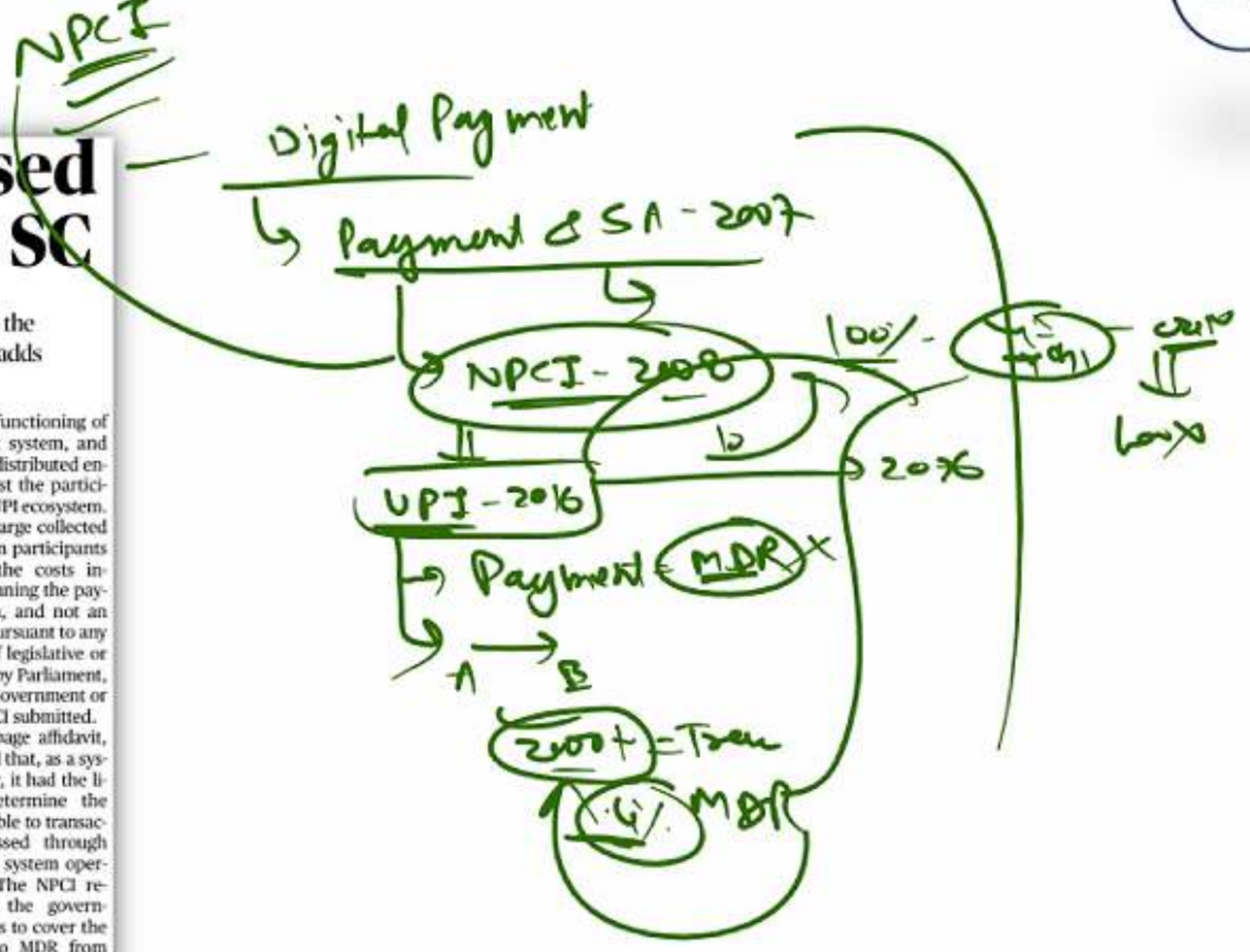
The affidavit said that the amended MDR framework targeted only higher value commerce without disturbing low-value transactions that drive the mass adoption of UPI. The MDR charge, which did not exceed 0.4%, would apply to P2M transactions above ₹2,000. "Effectively, MDR will apply to only about 4% of merchant transactions, and approximately 96% of all P2M will remain unaffected," the NPCI said.

'MDR is not a tax'

The NPCI countered the petitioners' contention that an amended MDR framework should have been introduced only through a new legislation and not just through a notification in September. It argued that MDR was not a tax, cess, fee, duty or any other statutory levy imposed by or under a legislative enactment. It was plainly a 'charge' collected to recover the huge costs associated with the functioning of the payment system, and was in turn, distributed entirely amongst the participants in the UPI ecosystem. "MDR is a charge collected by the system participants to recover the costs incurred in running the payment system, and not an imposition pursuant to any delegation of legislative or fiscal power by Parliament, the Central Government or RBI," the NPCI submitted.

In a 100-page affidavit, the NPCI said that, as a system provider, it had the liberty to determine the MDR applicable to transactions processed through the payment system operated by it. The NPCI recalled how the government's efforts to cover the costs of zero MDR from 2021-2022 through incentive schemes had been a huge financial strain on the public exchequer.

Further, the UPI Steering Committee, which includes third party application providers, had endorsed the MDR framework, the NCPI said.



महत्वपूर्ण तथ्य

Centre to set up panel to review UGC equity norms

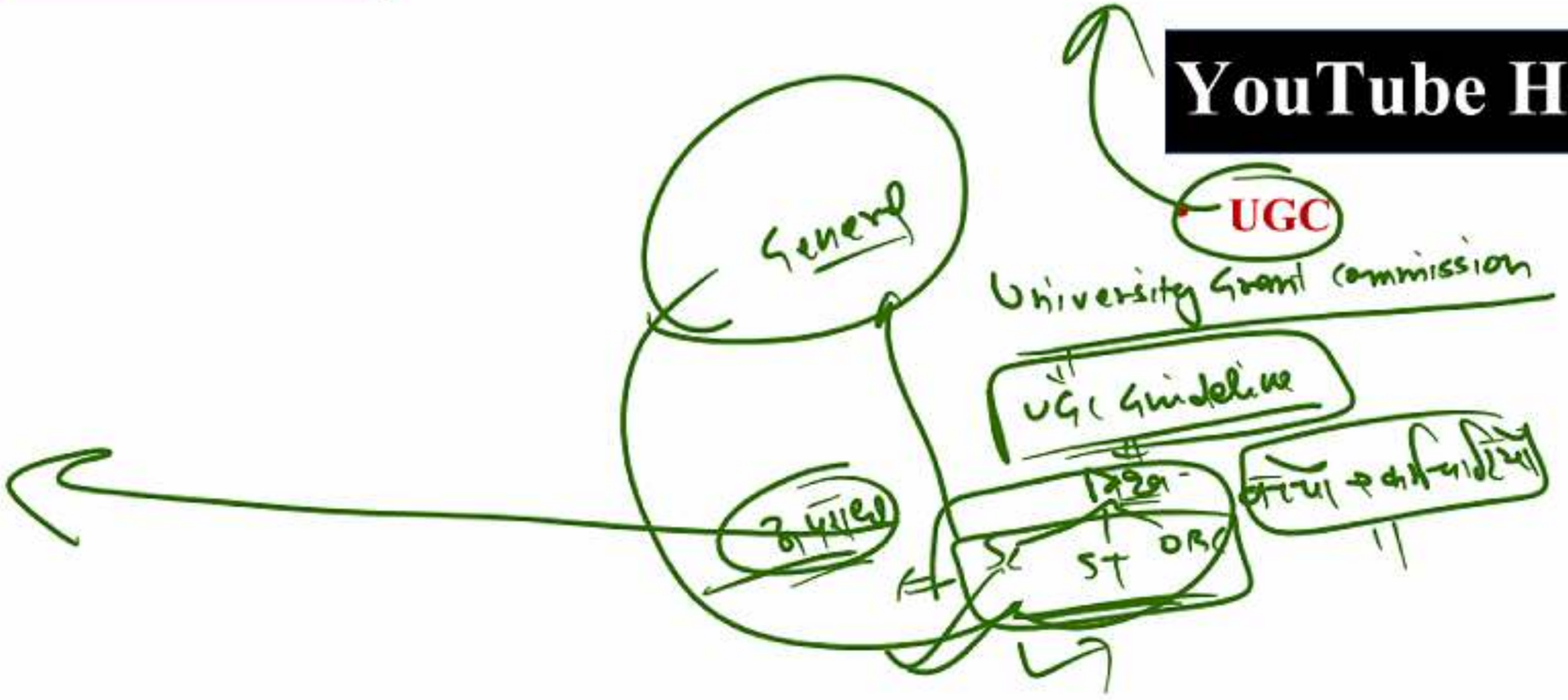
The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Union government is "contemplating" having a special committee review the University Grants Commission (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026, it said in a submission in the Supreme Court on Thursday. The Regulations were intended to fight discrimination within educational campuses, but had triggered protests by upper caste students claiming that the rules were one-sided.

In a brief hearing before a Bench headed by Chief Justice of India Surya Kant, Solicitor General Tushar Mehta, for the government, sought more time to come back with a comprehensive response, but added that the Centre was examining criticism about the 2026 Regulations.

In January 2026, the top court had stayed the Regulations, finding them "too sweeping" and vague. It had ordered that the University Grants Commission Regulations, 2012 would continue to be in force.

YouTube Homework



महत्वपूर्ण तथ्य

यूजीसी के नए नियम (UGC Equity Regulations 2026) क्या थे?

- अधिसूचना: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षण संस्थानों (कॉलेजों और विश्वविद्यालयों) में जातिगत भेदभाव को रोकने और समानता को बढ़ावा देने के लिए 13 जनवरी 2026 को नए नियम अधिसूचित किए थे।
- 2012 के नियमों में बदलाव: इन नए नियमों ने साल 2012 के पुराने नियमों की जगह ली थी।
- OBC का दायरा: इसमें पहली बार अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों और कर्मचारियों को भी सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया था।
- विवाद का कारण (धारा 3(c)): नियम 3(c) के तहत जाति-आधारित भेदभाव को केवल SC, ST और OBC के खिलाफ होने वाले पूर्वाग्रह तक सीमित किया गया था।
- नाराजगी और आरोप: सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों और संगठनों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी थी कि यह नियम एकतरफा है। इसमें सवर्ण/सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव या झूठी शिकायतों से बचाव का कोई प्रावधान नहीं था, जिससे इनका दुरुपयोग होने की आशंका जताई जा रही थी।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

- जनवरी 2026 में रोक: सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जनवरी 2026 में रोक (Stay) लगा दी थी। कोर्ट ने माना था कि इन नियमों की भाषा बहुत अस्पष्ट ('vague') है और इनके बहुत व्यापक व खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, जिससे समाज में बंटवारा हो सकता है।
- पुराने नियम लागू: कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगली सुनवाई या अंतिम फैसले तक परिसरों में साल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे।
- 5 नवंबर 2026 की सुनवाई: मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष जब यह मामला दोबारा सुनवाई पर आया, तो केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को जानकारी दी। कोर्ट ने चार सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी और जोर दिया कि हर विद्यार्थी के हितों की रक्षा होनी चाहिए।

सरकार ने क्या बदलाव या समीक्षा की बात कही है?

- विशेष समिति का गठन: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वह इन 2026 के नियमों की दोबारा समीक्षा करने के लिए एक विशेष उच्च-स्तरीय समिति (Special Committee) का गठन कर रही है।
- सभी वर्गों के हितों का ध्यान: सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि समिति इस बात पर विचार करेगी कि नियमों को कैसे संतुलित किया जाए ताकि छात्र समुदाय के किसी भी वर्ग (चाहे वो किसी भी जाति या श्रेणी का हो) को यह महसूस न हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है या उसे डराया जा रहा है।
- पुनर्विचार और पुनर्गठन: सरकार ने माना है कि छात्रों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नियमों के प्रारूप (Draft) और भाषा में बदलाव किए जाएंगे ताकि पारदर्शिता और संवैधानिक संतुलन बना रहे।

महत्वपूर्ण तथ्य



BUILDING BLOCKS

How do tokamaks work to make nuclear fusion possible?

A tokamak uses magnetic fields to confine superhot plasma to enable nuclear fusion, despite advances in research, engineering challenges remain, and no tokamak has generated net energy for commercial power

Jacob Kosby

A tokamak is a device that uses magnetic fields to trap very hot plasma inside a ring-shaped vacuum chamber. Plasma, a fourth state of matter, is a gas whose atoms have been stripped of their electrons, leaving free electrons and charged nuclei. The word comes from a Russian acronym describing a toroidal ring-shaped chamber with magnetic coils. The best-known fusion energy project in the world, the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), uses this design.

What problem does tokamak solve?

Nuclear energy today comes almost entirely from fission, the controlled chain reaction of uranium atoms, but fusion has always been theoretically possible and a subject of consistent long-term investigation by scientists. When light atomic nuclei such as deuterium and tritium, two isotopes of hydrogen and the best-studied candidates, join, they form helium and a fast neutron. But even this simple merger requires temperatures hotter than the sun's core, which no earthly material can contain. In physics, this is called the problem of containment. Contact with a wall would also cool the plasma and contaminate it with impurities. Plasma, being made of charged particles, can be steered by magnetic fields, and a tokamak uses that property to hold it away from the walls long enough for fusion to occur.

Who first conceived it?

The concept was developed in the Soviet Union in the early 1950s, largely credited to physicists Igor Tamm and Andrei Sakharov.

Experimental work followed at the Kurchatov Institute in Moscow, where the first machines operated in the late 1950s and, once word of its potential spread, it was adopted by research programmes in several universities.

Why is it shaped the way it is?

Charged particles in a magnetic field spiral around the field lines. In a straight tube, they would simply travel along the lines and escape through the ends, but bending the tube into a closed ring removes the ends, making the field lines loop back on themselves.

A ring alone does not work, however. The field from coils around a ring is stronger on the inner side than on the outer, which makes ions and electrons drift in opposite directions, up and down. This creates an electric field that pushes the whole plasma outwards into the wall.

The tokamak gets around this by driving a large electric current through the plasma itself, typically induced by a central magnet acting like a transformer. This current produces a second magnetic field that twists the field lines into a helix around the ring. Particles following a twisted line spend time at both the top and the bottom, which cancels the drift. A tokamak therefore combines two fields: one running around the ring, from external coils, and a twisting one from the plasma current. Additional coils shape and position the plasma.

How does all this create useful energy?

The plasma is kept away from the walls, but the energy it releases is not. In fact, the design depends on that energy reaching them. In a deuterium-tritium reaction, about 80% of the 17.6 MeV (million electron-volts) released goes to the neutron and about 20% to the helium nucleus (alpha particle). A kilogram of this fuel would release about 3.4 × 10^{14} J: if fully fused, roughly 80 million times the energy in the same quantity of coal.

In a power plant design, the inner wall is backed by a thick layer called a blanket. The neutrons slow down in it and deposit their energy as heat, much as in a boiler reactor's core. A coolant, such as water or helium, carries the heat out to make steam and spin a turbine, as in a conventional power plant. The blanket also contains lithium, because striking lithium produce tritium, which is rare and radioactive, so a plant would breed its own fuel this way.

Why haven't tokamaks so far produced the energy?

The principles are well understood, but the engineering challenges are formidable. ITER is backed and run by seven members — China, the European Union, India, Japan, South Korea, Russia and the United States — representing more than 30 countries. It has been plagued by delays and funding, and its projected costs, which were €5 billion in 2009, have increased at least fourfold.

ITER has not been switched on. It is still being assembled at Cadarache in France, so it has had no chance to succeed or fail. It is designed to produce about ten times the heating power fed into its plasma, but only once it begins deuterium-tritium operation. Deadlines are constantly shifting. In 2024, the project moved the start of research operations to 2034 and deuterium-tritium operation to 2039, adding about €5 billion in costs. Officials attributed this to the Covid-19 pandemic, supply-chain and quality problems, and "over-optimistic planning" for a first-of-a-kind machine. Even when it runs, ITER is a physics experiment and will not convert heat into electricity.

What about China?

China's EAST tokamak in Hefei sustained a high-confinement plasma for 1,066 seconds in January 2025, a record for duration, with electron temperatures of about 100 million degrees. In January 2026, it reported running at plasma densities well above a long-standing empirical limit. EAST is a physics machine, though, and has not generated net energy.

How many tokamaks does India have?

The two main machines are at the Institute for Plasma Research (IPR) in Gandhinagar. ADITYA, India's first tokamak, began operating in 1989 and was rebuilt as ADITYA-U, which resumed operations in 2012. SST-1, the Steady State Superconducting Tokamak, produced its first plasma in 2013 and uses superconducting magnets. India is also a member of ITER and manufactures components for it. Bengaluru-based Pranos Fusion has unveiled PRANOS, which it describes as India's first privately developed compact tokamak. The experimental machine is intended to develop capabilities in plasma control and magnetic confinement, rather than generate commercial electricity.

Are there alternatives?

Fusion research broadly follows two approaches: magnetic confinement, which includes tokamaks, and inertial confinement.

Stellarators also use a ring, but create the twisted field entirely with complex external coils rather than a plasma current. This allows steadier operation and avoids some instabilities, but the coils are harder to design and build. Germany's Wendelstein 7-X is the best-known example.

Inertial confinement, which doesn't use tokamaks at all, compresses a tiny fuel pellet with lasers or other beams so quickly that fusion occurs before the fuel can fly apart. The U.S. National Ignition Facility used this approach in 2022 to claim the production of "net energy". Other magnetic designs include mirror machines, which use open-ended fields, and compact configurations such as field-reversed configurations that have no central hole.

Tokamaks

महत्वपूर्ण तथ्य

- **टोकामैक क्या है और कैसे काम करता है?:** यह चुंबकत्व (magnetic fields) का उपयोग करके अत्यधिक गर्म 'प्लाज्मा' को एक छल्ले (donut-shaped) के आकार में सीमित रखने वाला उपकरण है, जिससे परमाणु संलयन (nuclear fusion) संभव हो पाता है।
- **परमाणु संलयन (Nuclear Fusion):** इसमें हाइड्रोजन के दो समस्थानिकों (ड्यूटेरियम और ट्रिटियम) को मिलाकर हीलियम और अत्यधिक ऊर्जा बनाई जाती है। प्लाज्मा का तापमान सूर्य के कोर से भी अधिक होता है, इसलिए इसे दीवारों से दूर रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है।
- **इतिहास और ITER:** इस अवधारणा का विकास 1950 के दशक में सोवियत संघ के भौतिकशास्त्रियों (इगोर टैम और आंद्रेई सखारोव) द्वारा किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग फ्रांस में बन रहा **ITER** प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत सहित 7 सदस्य शामिल हैं।
- **चुनौतियाँ और वर्तमान स्थिति:** अभी तक कोई भी टोकामैक वाणिज्यिक उपयोग के लिए 'नेट पॉजिटिव ऊर्जा' (जितनी ऊर्जा दी गई उससे अधिक ऊर्जा) उत्पन्न नहीं कर पाया है। ITER की समयसीमा और बजट कई बार बढ़ा है (अब 2039 तक ट्रिटियम ऑपरेशन का लक्ष्य)।
- **भारत में टोकामैक:** भारत के पास **ADITYA-U** और **SST-1** (IPR गांधीनगर) जैसे टोकामैक हैं। इसके अलावा बेंगलुरु के प्राइवेट स्टार्ट-अप प्रणोस फ्यूजन (Pranos Fusion) ने निजी तौर पर **PRAGYA** नामक टोकामैक का अनावरण किया है।
- **अन्य विकल्प:** संलयन के लिए टोकामैक के अलावा **स्टेलरेटर (Stellarators)** और लेज़र-आधारित **जड़त्वीय परिसीमन (Inertial Confinement)** जैसी तकनीकों पर भी काम चल रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

Eisenkot closer to forming govt. in Israel with backing of Arab lists

Joint List bagged 11 seats and Ra'am won 8 seats in election; in October 27 polls, neither Netanyahu nor Eisenkot secured enough votes for majority; once President gives mandate to a lawmaker, the person will have 28 days to form government

Agence France-Presse
JERUSALEM

Israel's largest Arab list on Thursday said it would back Gadi Eisenkot to form the next government, bolstering his chances of being picked over Prime Minister Benjamin Netanyahu, who lost the support of an allied religious party.

President Isaac Herzog was holding a second day of consultations with political parties after the October 27 election, in which neither Mr. Netanyahu – a polarising right-winger who has led Israel through three years of war – nor Mr. Eisenkot – a former military chief promising to restore national unity – secured enough votes for a majority.



Differing voices: Protesters in Jerusalem call for the formation of a Netanyahu-Eisenkot unity government, on Thursday. AP

Mr. Herzog will choose by himself whom to ask to form a new government, but traditionally the mandate is given to the person recommended by more parties, which would be Mr. Eisenkot.

Arab-majority lists won an unprecedented 19 seats in the election, making them potential kingmakers if Mr. Eisenkot's Opposition chooses to work with them – something which remains unclear.

Both Arab lists on Thursday said they were backing Mr. Eisenkot.

The Joint List, which bagged 11 seats, said in a statement that "it will inform the President of the State, Isaac Herzog, this evening of its decision to recommend that Gadi Eisenkot be tasked with forming the government".

Ra'am, which won eight seats, also endorsed Mr. Eisenkot.

Meanwhile, United Torah Judaism, which backed Mr. Netanyahu after the previous five elections, in its meeting with Mr. Herzog declined to recommend Mr. Netanyahu again as Prime Minister, although it also did not side with Mr. Eisenkot.

Observers say United Torah Judaism's tactic is likely aimed mostly at punishing Mr. Netanyahu and showing that their votes cannot be taken for granted.

Once Mr. Herzog gives his mandate to a lawmaker, the person will have 28 days to form a government, with a potential 14-day extension.

YouTube Homework

PR – क्या है
– उदा।
– भारत में किन-किन चुनावों में प्रयोग

महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

Saudi Arabia issues alerts, warns of 'danger' in Yanbu

Reuters
RIYADH



Fighters from the Saudi-led coalition hold a position during clashes with Houthis in Yemen's northwestern Jawf province. AFP

Saudi Arabia issued alerts on Thursday warning of potential danger in Yanbu, the kingdom's Red Sea oil export hub, as Yemen's Houthis (Ansar Allah) continue attacks on the kingdom that have opened another front in the U.S.-Israeli war on Iran.

The Saudi-led coalition fighting the Houthis in Yemen said it destroyed a missile launched by the group towards Islam's holy city of Medina.

"Air defence intercepted and destroyed a ballistic missile launched by the terrorist Houthi militia toward the Medina region," coalition spokesperson Turki al-Malki said in a post on X.

The Houthis rejected any suggestion they were targeting the city, saying such accusations were a "blatant and grave falsehood". "Our operations target only its oil facilities and military bases."

The kingdom's civil defence also issued emergency alerts for the southeastern area of Sharurah that borders Yemen.

Houthis said on Wednesday they had attacked Riyadh's international airport while Syria's President Ahmed al-Sharaa visited the kingdom.

Saudi Arabia, the world's biggest oil exporter and a key U.S. ally, has been requesting assistance from countries for support in its renewed war against the Yemeni militia.

महत्वपूर्ण तथ्य

UN peacekeeping mission prepares to exit Western Sahara after 35 years

Associated Press
LAAYOUNE

The UN peacekeeping mission in the disputed territory of Western Sahara will start repatriating personnel, closing a dozen facilities and disposing of equipment as part of a "liquidation phase" following a U.S.-Russia standoff at the Security Council last week.

The mission's abrupt end after 35 years raises questions about security and stability in the region. Western Sahara is a vast desert nearly the size of Colorado and rich in fisheries and minerals. The contested resource corridor once ruled by Spain is now claimed by both Morocco and the pro-independence Polisario Front.



Disputed land: Western Sahara is a vast desert nearly the size of Colorado and rich in fisheries and minerals. AFP

UN peacekeeping chief Jean-Pierre Lacroix said late Wednesday that the department dealing with operational issues of the UN's far-flung peacekeeping missions wants to ensure an "orderly" retreat. "And we count, of course, on the full cooperation of all the parties."

The UN mission, known as MINURSO, was established in 1991 to monitor a ceasefire between Morocco and the Polisario Front and organise a referendum on self-determination.

But the vote never materialised, as the two sides failed to agree on who would be eligible to participate. The ceasefire collapsed in 2020, and the UN says the region remains marked by tensions and low-intensity hostilities.

During the mission, 20 UN personnel lost their lives. The UN force was authorised to have 534 personnel, and its 2026-2027 budget was more than $62 million. The top military contributors to the force were Egypt, Ghana and Pakistan.

Morocco's royal palace, which oversees the country's foreign policy, welcomed the mission's end, saying it had failed to monitor the ceasefire. The Polisario Front and Algeria, meanwhile, regretted the decision not to renew its mandate.

महत्वपूर्ण तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UN Peacekeeping Force) वैश्विक संघर्षों को सुलझाने और शांति बनाए रखने का एक बेहद महत्वपूर्ण जरिया है।

1. स्थापना और मुख्य उद्देश्य

- स्थापना: संयुक्त राष्ट्र (UN) के पहले शांति मिशन की स्थापना मई 1948 में हुई थी। इस मिशन का नाम UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) था, जिसे मध्य पूर्व (Middle East) में इजरायल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्धविराम की निगरानी के लिए तैनात किया गया था।
- उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य संघर्ष प्रभावित देशों में स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। ये मिशन सहमति, निष्पक्षता और आत्मरक्षा (या जनादेश की रक्षा) को छोड़कर बल का प्रयोग न करने के सिद्धांतों पर काम करते हैं। इनके कार्यों में नागरिकों की रक्षा करना, शांति समझौतों की निगरानी करना, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना और मानवाधिकारों की रक्षा करना शामिल है।

2. किन-किन क्षेत्रों में सहायता दी?

- UN शांति सैनिकों (जिन्हें उनके नीले हेलमेट के कारण 'ब्लू हेलमेट' भी कहा जाता है) ने दुनिया भर के कई तनावग्रस्त क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं:
- एशिया: भारत और पाकिस्तान (UNMOGIP - कश्मीर में युद्धविराम की निगरानी), कंबोडिया।
- अफ्रीका: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (MONUSCO), दक्षिण सूडान (UNMISS), सोमालिया, लाइबेरिया।
- मध्य पूर्व व यूरोप: लेबनान (UNIFIL), गोलान हाइट्स (UNDOF), साइप्रस (UNFICYP), कोसोवो (UNMIK) आदि।
- इनकी ऐतिहासिक सफलता और वैश्विक योगदान के लिए इन्हें 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

4. सहारा (Western Sahara) से बाहर निकलने की बात क्यों हुई है?

- हाल ही में (अक्टूबर/नवंबर 2026), संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी सहारा (Western Sahara) में काम कर रहे अपने 35 साल पुराने शांति मिशन MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) को बंद करने और वहां से बाहर निकलने (Liquidation Phase) की घोषणा की है।

ऐसा क्यों किया गया (कारण):

- यह फैसला किसी रणनीति के तहत नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अमेरिका और रूस के बीच राजनीतिक गतिरोध (Standoff) के कारण हुआ है:
- जनादेश (Mandate) का नवीनीकरण न होना: UN शांति मिशन को काम जारी रखने के लिए सुरक्षा परिषद से हर साल मंजूरी (Mandate Renewal) की जरूरत होती है। 31 अक्टूबर 2026 को इस मिशन की अवधि समाप्त हो रही थी।
- अमेरिका और रूस का वीटो (Veto): अमेरिका ने एक प्रस्ताव पेश किया था जो पश्चिमी सहारा पर मोरक्को (Morocco) की संप्रभुता/स्वायत्तता योजना का समर्थन करता था। इस पर रूस ने वीटो लगा दिया, क्योंकि रूस का मानना था कि यह एकतरफा फैसला है। इसके बाद अमेरिका ने रूस के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें मोरक्को की संप्रभुता का जिक्र किए बिना मिशन को आगे बढ़ाने की बात थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

Ronaldo bids adieu to the international stage

The Portuguese icon leaves as the highest scorer ever with 146 goals but his prowess has been on the wane of late; the 41-year-old has had a fall-out with national coach Jesus recently

FOOTBALL

Agence France Presse
LISBON

Portuguese football legend Cristiano Ronaldo announced on Thursday that he was retiring from international football at the age of 41. Ronaldo played 234 times for Portugal and scored 146 goals – a world record.

But the forward's powers have been waning in recent years and he fell out with national coach Jorge Jesus last month after he refused to play him in a Nations League match.

Ronaldo left the team camp and was handed a 30-day suspension.

Although it was rumoured that he intended to return to the international fold, on Thursday the five-time winner of the Ballon d'Or released a video on his Instagram account in which he said he was ending his international career.

"To the Portuguese people, the day has come for me to hand back the number seven shirt of our national team," Ronaldo said, as images of his career were played. "I never felt it belonged to me alone, but for 23 years I had the privilege and the responsibility of wearing it, defending it and carrying it with me into stadiums all around the world," he continued.

"Today the time has come to pass it on to the future. It was not an easy decision, because some decisions are not made with the mind alone – they are also made with the heart."

In the highlight of his international career, Ronaldo won the 2016 European Championship with Portugal in France, although he had to leave the field during the final with an injury.

Ronaldo's journey in numbers

234 appearances | **146** goals | **46** assists

- 1 Ronaldo is the only player to score at six World Cups (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)
- 1 His first Portugal goal came in his eighth appearance when he headed home in the 83rd minute in the 1-1 loss to Greece in the group stage at Euro 2004
- 1 He is the first to score 100 goals for a national team in European international competitions
- 1 His only red card came 13 years into his career when he was booked for elbowing Dara O'Shea in a 0-2 World Cup qualifying defeat to Ireland in Dublin in November 2025
- 5 Ronaldo is the only player to score at five different European championships
- 14 He has netted the most goals at the European championship and is also the leading scorer in qualifying (55)
- 6 He played in six World Cups, Messi the other to do so
- 23 Ronaldo has scored at least one goal in 23 consecutive years
- 6 Ronaldo holds the record for most appearances at European championships (2004, 2008, 2012, 2016, 2020 and 2024)
- 124 His goals in competitive matches, a strike rate of 84.9%. Messi's is 93.8%
- 146 Number of international goals, a men's world record. The next highest for Portugal is Pauleta, with 47 goals in 88 appearances.
- 10 He is the first man to perform 10 hat-tricks in international football
- 11 Ronaldo is Portugal's all-time leading World Cup scorer
- 200 Ronaldo is the first man to reach 200 international caps.
- 234 His appearances, a men's world record
- **2003** Ronaldo made his international debut at the age of 18 in a friendly against Kazakhstan on August 20, 2003. He replaced Luis Figo at half-time
- **2019** His most productive year for Portugal as he found the target 14 times in 12 matches

Compiled by Anirudh Sreeram

CR7 — the epitome of sheer drive, relentlessness and athleticism

P.K. Ajith Kumar

First Lionel Messi. Now Cristiano Ronaldo. Within a space of three months, two of the all-time greats have called time on their international careers.

International football will never be quite the same again. How could it be without the genius of Messi that creates something out of nothing and the force, pace and brutal elegance of Ronaldo?

We have been fortunate that their extraordinary careers blossomed right in front of our eyes, that we could watch them score all those incredible goals over the last couple of decades, at the World Cups, in European leagues. True, everyone loves to love Messi. Ronaldo may not be universally cherished like the way the Argentine is, but his fan-following is no less committed.

Modesty may not be his best quality, he may have been accused of diving, he may have been theatrical, but make no mistake, few have played the beautiful game with as much passion, with as much hunger.

In fact, when it comes to the sheer drive and the relentless pursuit in the perfection of their art and athleticism, you would not too find many like Ronaldo in all sports, not just football. Closer home, he reminds you of one sporting great, though.

That man, Virat Kohli, like Ronaldo, has defied age. Not surprising really that the Indian superstar admires the Portuguese superstar.

If football was more of an individual game within a team game, like cricket, Portugal would have won more tournaments. A Kapil Dev could defeat Zimbabwe. A Glenn Maxwell could beat Afghanistan.

Football is as much a team game as any. Just the other day, Borussia Dortmund great Marcel Schmelzer had told this correspondent during an interview, that he was not a fan of the Ballon d'Or, as he believed football was a team game, it was not about individuals.

Still, the individual brilliance of Ronaldo made Portugal a formidable force. He led Portugal all the way to the Euro title in 2016.

He sadly had to leave the field after just 25 minutes in the final against France, but he cheered his teammates from beyond the boundary. It was Portugal's finest hour.

With Ronaldo, the Portuguese played in every World Cup between 2006 and 2026 (before him they featured in only three).

And he provided some unforgettable moments at the world's greatest spectacle.

Remember that hat-trick against Spain in 2018? You would not have forgotten that insane free kick in the 88th minute that made the score 3-3.

It was genius. It was magic. It was Ronaldo.



One of a kind: Ronaldo had many critics but few can doubt his passion for the game. AP

महत्वपूर्ण तथ्य

DRDO carries out successful flight-test of Pralay missile

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Defence Research and Development Organisation (DRDO) on Thursday successfully flight-tested the indigenously developed quasi-ballistic missile Pralay from Dr. APJ Abdul Kalam Island off the Odisha coast. The successful trial paved the way for its imminent induction into the armed forces.

According to Ministry of Defence, the missile was test-fired at around 11.10 a.m. as part of user evaluation trials. All test objectives were fully met, as confirmed by data captured through various range instruments deployed by the Integrated Test Range (ITR), Chandipur, the Defence Ministry said.

Defence Minister Rajnath Singh congratulated DRDO, the armed forces and industry partners on the successful test.

DRDO ⇒ Pralay missile
(पृथ्वी)
quasi-ballistic missile

महत्वपूर्ण तथ्य



INS Sahyadri reaches Japan for MALABAR naval exercise

The Indian Navy's indigenous stealth frigate *INS Sahyadri* arrived at Yokosuka Naval Base in Japan on Wednesday to participate in the multilateral naval exercise MALABAR 2026, which brings together the navies of India, Japan, the United States, and Australia. According to the Indian Navy, the warship, part of the Eastern Fleet, was accorded a warm welcome by the Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF). The exercise will provide an opportunity to the participating navies to enhance operational coordination, strengthen interoperability and exchange professional expertise through a series of engagements during the harbour and sea phases.

MALABAR — USA, Aust, Japan, India } = Sahyadri

महत्वपूर्ण तथ्य



ग्रामीण विकास मंत्रालय

विकसित भारत-जी राम जी के अंतर्गत चारा उत्पादन बढ़ाने, पशुधन संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) की संयुक्त पहल

केंद्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में चारे की उपलब्धता बढ़ाने और पशुधन विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किया संयुक्त परामर्श (एडवाइजरी)

चारा उत्पादन, चारागाह विकास, डेयरी संबंधी बुनियादी ढांचे और पशु चिकित्सा सुविधाओं के लिए 22 अनुमेय कार्यों(परमिसिबल वर्क्स) चिन्हांकित

राज्यों को चारा एवं पशुधन संबंधी कार्यों पर कुल कार्यक्रम व्यय का कम-से-कम 5 प्रतिशत खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया गया

प्रविष्टि तिथि: 05 NOV 2026 10:22AM by PIB Delhi

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत अभिसरण (कन्वर्जेंस) के माध्यम से चारा सुरक्षा, चारागाह विकास और पशुधन को सहयोग देने वाले बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संयुक्त रूप से एक परामर्श (एडवाइजरी) जारी की है।

यह पहल चारे की कमी को दूर करने, पशुधन से जुड़ी बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों तथा पशुधन एवं डेयरी गतिविधियों पर निर्भर भूमिहीन परिवारों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण (होल-ऑफ-गवर्नमेंट अप्रोच) को अपनाया गया है। इसके तहत ग्रामीण रोजगार और गांवों में परिसंपत्तियों के निर्माण को पशुधन क्षेत्र की जरूरतों से जोड़ा जाएगा। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कार्य अधिनियम के प्रावधानों और निर्धारित योजना के अनुरूप हों।

महत्वपूर्ण तथ्य

रक्षा मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

आईपीआरडी-2026 सहयोगात्मक महासागर शासन और जिम्मेदार समुद्री प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ संपन्न

प्रविष्टि तिथि: 05 NOV 2026 7:20PM by PIB Delhi

तीन दिवसीय भारतीय नौसेना का वार्षिक उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक संवाद, इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद 2026(आईपीआरडी-2026), **05 नवंबर 2026** को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन(एनएमएफ) के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में, क्षेत्रीय समुद्री सहयोग के लिए व्यावहारिक रास्ते तलाशने के उद्देश्य से, पांच पेशेवर विषयगत सत्रों और वरिष्ठ-स्तरीय चर्चाओं के माध्यम से *'इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग'* पर विचार-विमर्श किया गया।

समापन दिवस का शुभारंभ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि के विशेष संबोधन के साथ हुआ, जिसके बाद सीडीएस ने श्रोताओं के साथ एक विचार-विमर्श सत्र में भाग लिया। इसके पश्चात 'महासागर शासन और समुद्री सुदृढ़ता के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण' विषय पर एक सत्र आयोजित किया गया, जिसका संचालन यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह(सेवानिवृत्त) ने किया। इस सत्र में फिलीपींस विश्वविद्यालय की प्रोफेसर देवो फ्लोरेंस ओंडा ने महासागर शासन के क्षेत्र में फिलीपींस के अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक सहयोगात्मक योजना पर अपने विचार रखे। अंतरराष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण में पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ डॉ. मैरी बोरेल-मैककिनन ने गहरे समुद्र में अनुसंधान संबंधी समानतापूर्ण साझेदारियों और संसाधन शासन के मुद्दों का विश्लेषण किया। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन(सीडीआरआई) के श्री रामराज नरसिम्हन ने अवसंरचना रोधी द्वीपीय राज्यों(आईआरआईएस) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी, जबकि स्वीडन की फ्यूचर मैरीटाइम की सुश्री सोफिया फर्स्टेनबर्ग-स्टॉट ने इस बात पर विचार व्यक्त किए कि समुद्री विज्ञान और जहाजरानी संचालन के बीच समन्वय को किस प्रकार मजबूत किया जा सकता है। इस सत्र में एक साझा चुनौती के चार प्रमुख आयामों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें वैज्ञानिक क्षमताओं को शासन व्यवस्था से जोड़ने, अनुसंधान साझेदारियों को अधिक समानतापूर्ण बनाने, संवेदनशील द्वीपीय देशों की आपदा-सहनशीलता को मजबूत करने तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता शामिल थी कि वैज्ञानिक ज्ञान समुद्री उद्योग और सार्वजनिक संस्थानों के निर्णयों का आधार बने।

नौसेना

IPRD-2026

3-5 NOV

महत्वपूर्ण तथ्य

रेल मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

रेल मंत्रालय ने वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चले समारोह का समापन किया

चार चरणों में आयोजित इस समारोह के तहत सामूहिक गायन, निबंध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी और तिरंगा रैली का आयोजन किया गया

प्रविष्टि तिथि: 05 NOV 2026 7:59PM by PIB Delhi

रेल मंत्रालय ने वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित साल भर के समारोह के चौथे चरण (समापन सप्ताह, 1 -7 नवंबर 2026) के तहत आज रेल भवन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ श्री सतीश कुमार, बोर्ड के सदस्य, महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी उपस्थित रहे।



150 वन्दे मातरम्

Home Assignment

- ❑ National Safety Day
- ❑ PM- SBM

स्वच्छ भारत मिशन

Thanks For Watching

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Subscribe Now

Stay Connected

Learn
Share
Grow
Together ♡

Better
Students
Brighter
Tomorrow

DISCIPLINE
CONSISTENCY
SUCCESS

Small
Steps
Big
Results